



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ई0 (माघ 29, 1944 शक सम्वत) [संख्या-07

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक बच्चा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य -	-	₹0
भाग 1-विज्ञप्ति-उपकारा, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	137-191	3075
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के सञ्चालन योगदाय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	36-38	1500
भाग 2-आज्ञाएँ, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उदारण	-	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नीटीकाइच एरिया, टाउन एरिया एवं निर्धारित (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया	01-02	975
भाग 4-निदेशक, रिकार्ड विभाग, उत्तराखण्ड	-	975
भाग 5-एकार्चन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	-	975
भाग 6-विल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट करेटियों की रिपोर्ट	-	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुधित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	-	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि	177-200	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि	-	1425

भाग १

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग-१

विज्ञप्ति / पदोन्नति

28 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 1351/XX-1-2022-2(32)2003-एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग में पुलिस चप महानीरीक्षक, वेतन मैट्रिक्स स्तर-13ए के रिक्त ०१ पद एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या ४५१०६ (Comp. No. 29197) दिनांक 21.12.2022 द्वारा सूचित ०१ अस्थायी पद (कुल ०२ पदों) के सापेक्ष सम्बन्धित विचारोपरान्त निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-३ में अंकित तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं वैच वर्ष	अनुभव्यता की तिथि
१	२	३
१.	श्री दलीप सिंह कुवर, (IPS:SPS 2009)	०१.०१.२०२३
२.	श्री धर्मपाल, (IPS:SPS 2009)	०१.०१.२०२३

विज्ञप्ति / पदोन्नति

28 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 1352/XX-1-2022-2(32)2003-एतद्वारा, भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग के अधिकारी, श्री सुखबीर सिंह, (IPS:SPS-2010) को चयन वेतनगान (Selection Grade) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 के पद पर सम्बन्धित विचारोपरान्त दिनांक ०१.०१.२०२३ से पदोन्नति प्रवान किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आशा से,

राधा रत्नौरी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग-१

कार्यालय आदेश

02 जनवरी, 2023 ई०

संख्या ।/87492/2022-शासनादेश संख्या ३४०७/III-५००(६).४६ दिनांक ०६ नवम्बर, १९४६ (Manual of Government Orders के प्रस्तर-२५०) के पावधानों के अधीन श्रीमती विमा दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक का विवाह होने के स्परान्त श्रीमती विमा दीक्षित के सेवा अभिलेखों में उनका नाम 'विमा दीक्षित' के स्थान पर 'विमा पाण्डे' अंकित किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राधा रत्नौरी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह (अधिकारी) अनुमान-03

अधिसूचनानियुक्ति

18 जानवरी, 2023 ई०

संख्या 91744/XX-3 / 2023-02(06) / 2009-उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिहार द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी परीक्षा-2021 के अन्तर्गत सीधी मर्ती के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स का स्तर-10 (अपुनरीक्षित वेतनमान रु० 15600-39,100 + ग्रेड पे-रु० 5400) के पद पर इस विज्ञप्ति में अग्रेत्तर प्रस्तरों में उल्लिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1	श्री अभिनव त्यागी	श्री अंबरीश त्यागी	एच-322, रिलायस टाउनसिप, नागोथाने, रायगढ़, महाराष्ट्र। पिन कोड-402128
2	श्री ईशान कटारिया	श्री कटारिया आर०डी०	टावर-बी-2, फ्लैट नं०-1004, रेडिकोन वेदांतम, नोएडा एक्सटेंशन, सैकटर-18 सी, उत्तर प्रदेश। पिन कोड-201301
3	श्री गौरव किरार	श्री रघुवीर सिंह	प्राइड परपल कोरोनेट, द्वितीय तल, बाटा शोरूम के ऊपर, बाणेर, पुणे, महाराष्ट्र। पिन कोड-411045

2- उक्तानुसार नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त 'उ०प्र० अग्निशमन (राजपत्रित अधिकारी) सेवा नियमावली, 1984' (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित की जायेगी।

3- उक्त अभ्यर्थियों को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- अभ्यर्थियों द्वारा पत्र निर्गत होने की तिथि के 01 माह के भीतर उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। समुचित कारणों के बिना योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है और तदनुसार उनका अस्वर्थन निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

5- अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं/प्रमाण-पत्रों के साथ पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में योगदान प्रस्तुत किया जायेगा:-

- 1) केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।
- 2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
- 3) एक से अधिक जीवित पल्ली न होने का घोषणा—पत्र/शपथ—पत्र।
- 4) 'इण्डियन ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट, 1923' के ग्राविधानों को पढ़े जाने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र।
- 5) 'दो राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु अभ्यर्थी के सम्बन्धी न हों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण—पत्र।
- 6) शैक्षिक योग्यता एवं स्थार्ड निवास प्रमाण—पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

6— पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने से पूर्व 'राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड' से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

7— नियुक्ति के उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा यथानिर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण/विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा।

7— अभ्यर्थियों की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

राधा रत्नौली,
अपर मुख्य सचिव।

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

25 नवम्बर, 2021 ई०

संख्या 9539/तीन-44/रायो/2018-19-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व वन्यजाग-3, देहरादून के रायो-707/XVIII(3)/2021-03(10)/2018, दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जीत चकवन्दी अधिनियम-1953 (उप्रोअधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-83/31-A-813-1854-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर, 1958 द्वारा यथाप्रतिनिधित्व अधिकारों का प्रयोग करते हुये में, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकवन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून, जनपद हरिद्वार, तहसील लक्ष्मण के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4(2) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2558/तीन-44/रायो/2018-19, दिनांक 12 सितम्बर, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद हरिद्वार की तहसील हरिद्वार परगना ज्यालापुर के ग्राम कटारपुर अलीपुर को चकवन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये उक्त ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्वारा निरस्त करता हूँ।

विज्ञाप्ति

18 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 4701/तीन-८०/च०सं०/2022-२३-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-३, देहरादून के शा०सं०-१०६७/XVIII(3)/2022-०३(१०)/2016, दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-५, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की घारा-६ की उपधारा-(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-८३/३१-८१३-१९५४-Rev(A) दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, चन्द्रेश कुमार, संचालक चकवन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून, जनपद हरिद्वार, तहसील लक्सर के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की घारा-४(२) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-१६९/मु०रा०आ०/(पक) /, दिनांक ०८ मई, २००३ में आंशिक संशोधन करते हुये जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर परगना मंगलौर के ग्राम सलेमपुर बकाल को चकवन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये उक्त ग्राम की विज्ञप्ति को एवंद्वारा निरस्त करता हूँ।

विज्ञप्ति

15 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 4644/तीन-२२/च०सं०/2021-२२-जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकवन्दी, हरिद्वार के पत्र संख्या-१२४/प०क०, दिनांक 12 जूलाई, 2022 से को गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकवन्दी अधिनियम, 1953 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-५, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की घारा-४ की उपधारा-(२) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या-३७४१/सी०प०च०आ०ई०ई०-४५४/६३, दिनांक २१ नवम्बर, १९६३ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके राजानादेश संख्या-१०८१/XVIII(3)२०२२-०७(२१)२००८, दिनांक ०८ दिसम्बर, 2022 के अनुपालन में, मैं चन्द्रेश कुमार, संचालक चकवन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून, एवं द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार के तहसील लड़की के नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकवन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गणठ भें प्रकाशित होने के दिनांक से चकवन्दी क्रियायें की जायेगी : -

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जिला
१.	कल्याणपुर उर्फ नारसन कलौं	लड़की	मंगलौर	हरिद्वार

चन्द्रेश कुमार,

संचालक, चकवन्दी /
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-०१

कार्यभार प्रमाणक

21 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 233/निःस०/अ०स०/2022-प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-०१, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश सं० File No PVD 1-IAS/JAG/1/2022-XXX-1 (Computer No 44239) 1/85119/2022 देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 के क्रम में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में कनिष्ठ प्रशासनिक वैतनमान रु० 15,600-39,100 + शेष पे रु० 7600/- (पे मैट्रिक्स लेवल-12) के पद का कार्यभार अधोहस्ताकारी द्वारा आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 के पूर्वाहन में यहां कर लिया गया है।

अधिसूचक अधिकारी

(चमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

प्रतिहस्ताकारिता,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव।

वित्त अनुभाग-८

अधिसूचना

26 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 86152/2022/07(100)/XXVII(8)/2008-मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीतात के संस्तुति पत्र रा०-5524/XIII-f-7/Admin.A/2004, दिनांक 16.12.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तराखण्ड भूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूल एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा-४ की उपधारा (2)(क) एवं उपधारा (4)(क)के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री मणिक गजहर सुल्तान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा को अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आङ्गा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

29 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 875 / VII-A-2 / 2022 / 17—उद्योग / 2013—राज्यपाल, औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1675 / VII-A-2/2021/17—उद्योग / 2013- दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 के क्रम में राज्य में लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाईयों/परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार सृजन हेतु प्रख्यापित मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति, 2021 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित परिचालन दिशानिर्देश बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 परिचालन दिशानिर्देश, 2022

अध्याय—एक

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं लागू होना (1) इन दिशानिर्देशों का संक्षिप्त नाम मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 परिचालन दिशानिर्देश, 2022 है। (संक्षेप में एमआईआईपी परिचालन दिशानिर्देश 2022)

(2) यह दिशानिर्देश मेगा औद्योगिक और निवेश नीति, 2021 प्रख्यापित होने की तारीख से अर्थात् 31 दिसम्बर, 2021 से प्रभावी होंगे तथा नीति की वैधता अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे।

(3) पात्र उद्यम/इकाईयां मेगा औद्योगिक एवं निवेश नीति, 2021 के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा के प्रारम्भ करने के दिनांक से नीति की वैधता अवधि के भीतर अधिकतम पांच वर्षों के लिए प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण: मेगा औद्योगिक और निवेश नीति—2016 (समय—समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत स्थापित/स्थापनाधीन नयी तथा विस्तारीकरण की परियोजनाओं/इकाईयों को उक्त नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 640 / 2016 / VII-1/17—उद्योग / 2013 दिनांक 28.07.2016 से प्रख्यापित मेगा औद्योगिक और निवेश नीति के परिचालन दिशा-निर्देश—2016 के प्राविधानों के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

2. परिभाषाएँ (क) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने से असिप्रेत है:

(i) नई इकाई के लिए वह तिथि जिस पर इकाई तैयार उत्पादों का पहला बिक्री बिल जारी करती है।

(ii) विस्तार के लिए निवेश करने वाली मौजूदा इकाई के लिए, वह तारीख जिस पर इकाई विस्तार के पूरा होने के बाद तैयार उत्पाद का पहला बिक्री बिल जारी करती है।

(x) "सक्षम प्राधिकारी" से क्रियान्वयन अभिकरण के अधिकारी अथवा अभिकरण अथवा प्रतिनिधि, जिन्हें नीति के क्रियान्वयन के लिए इन दिशानिर्देशों के अधीन विशिष्ट प्राधिकार सौंपे गये हैं, अभिप्रेत है ;

(y) "संवितरण अभिकरण" से उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक एवं आवेसंरचना विकास निगम लिमिटेड (संक्षिक्ष में सिडकूल) या ऐसे अन्य अभिकरण/विभाग जिन्हें समय-समय पर इस नीति के अन्तर्गत स्वीकृत अनुदान/वित्तीय प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु अधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है ;

(z) "विद्युत अधिभार" का अर्थ वही होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश विद्युत इलेक्ट्रीसिटी (अधिभार) अधिनियम, 1952 (उत्तराखण्ड अनुकूलन एवं उपान्तरण) आदेश, 2001 में परिभाषित किया गया है।

(a) "मौजूदा औद्योगिक इकाई" से ऐसी औद्योगिक इकाई, अभिप्रेत है जो दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 से पहले स्वनिर्भीत उत्पाद के व्यवसायिक उत्पादन तथा सेवा का प्रचालन कर रही हो तथा जिसने इकाई के विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण / विविधीकरण के लिए www.investuktarakhand.com पोर्टल पर संयुक्त आवेदन प्रक्रूप-1 पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सज्ज्य/जिला प्राधिकृत समिति के अनुमोदन से परियोजना के विरासत के लिए संदर्भान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो ;

(b) औद्योगिक क्षेत्र/सम्पदा/विशेष औद्योगिक संपदा या कोई अन्य अधिसूचित/चिह्नित भूमि से अभिप्रेत है;

(i) सिडकूल द्वारा विकसित औद्योगिक पार्क/आस्थान।

(ii) राज्य औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक आस्थान।

(iii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निजी औद्योगिक क्षेत्र / आस्थान / विशेष औद्योगिक आस्थान ;

(iv) राज्य में संबंधित विनियमित क्षेत्रों के जोनल मास्टर प्लान में औद्योगिक/वाणिज्यिक/और चिह्नित की गई सेवा गतिविधियों के उपयोग के लिए अधिसूचित और चिह्नित भूमि ;

(v) पात्र गतिविधियों के लिए विनियमित क्षेत्रों में अधिसूचित अथवा चिह्नित ऐसी भूमि, जिस पर परियोजना की स्थापना के लिए सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा भवन भान्चित्र को अनुमोदित कर दिया गया है ;

(vi) उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड) जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (समय-समय पर यथासंशोधित) की थारा 143 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित किया गया हो ;

(vii) "आद्योगिक/सेवा क्षेत्र" की इकाई से ऐसी कोई औद्योगिक इकाई/परियोजना अथवा पात्र सेवा क्षेत्र का उद्यम अभिप्रेत है जो कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अर्थात् एक पंजीकृत उद्यम हो तथा जिसकी स्थापना के लिए मारत सरकार, उद्योग संबद्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग (आद्योगिक सहायता संचालन) में आईईएम

पार्ट-ए (आशय पन्न अथवा इच्छा पत्र) दाखिल कर अमिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो ;

- (ज) "कार्यान्वयन एजेंसी" से उत्तराखण्ड सरकार का औद्योगिक विकास विभाग या महानिदेशक पूर्व आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड का कार्यालय, जिसे नीति के क्रियान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, अभिप्रेत है ;
- (क) "लार्ज प्रोजेक्ट" अथवा "लार्ज इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्करणों में रु. 50 करोड़ से रु. 75 करोड़ तक का स्थिर पूँजी निवेश किया गया हो ;
- (ब) "मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्करणों में रु. 75 करोड़ से रु. 200 करोड़ तक का स्थिर पूँजी निवेश किया गया हो ;
- (द) "विनिर्माणिक उद्यम" से औद्योगिक उपकरण या कोई अन्य प्रतिष्ठान, जो भी नाम से जाना जाता है, किसी भी तरह से माल के निर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है, जो उद्योगों (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951) (1951 का 55) की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी उद्योग से सम्बन्धित है और जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में विनिर्माणिक उद्यम के रूप में परिभाषित किया गया हो, अभिप्रेत है ;
- (६) "नई औद्योगिक इकाई" से वह औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसने 31 दिसम्बर, 2021 से पहले लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजना की स्थापना के लिए एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत www.investuttarakhand.com पोर्टल पर संयुक्त आवेदन प्रक्रिया-१ पर आवेदन कर राज्य/जिला प्राधिकृत समिति के अनुसूचन से परियोजना की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की हो ;
- (७) "नई परियोजना/इकाई" से वह परियोजना/इकाई जिसने मेगा औद्योगिक और निवेश नीति-2021 (एमआईआईपी-2021) की वैधता अवधि के दौरान स्थापित होकर अपना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है ;
- (८) "नोडल अधिकरण" से उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड में राज्य उद्योग मित्र प्रकोष्ठ अथवा एकल खिड़की व्यवस्था प्रकोष्ठ अभिप्रेत है, जिसे इस नीति के अन्तर्गत आवेदनों को प्राप्त करने, समुचित स्तर पर आवेदनों की संवीक्षा/परीक्षण तथा स्वीकृति के लिए अग्रसारित/प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया हो ; उद्योग निदेशालय या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी नोडल अधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ;
- (९) "नीति" से मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्चेस्टमेंट नीति, 2021 अभिप्रेत है ;

(६) "संवीक्षा समिति" से इन दिशानिर्देशों के संलग्नक परिशिष्ट-क में यथाउलिलिखित दिशानिर्देश और नीति के अधीन प्राप्त आवेदनों और दावों की संवीक्षा के लिए गठित समिति अभिप्रेत है।

(७) "सेवा उद्यम" से सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे हुए ऐसे उद्यम, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 में परिभाषित किया गया हो और यह यात्रिविधि इस नीति के अन्तर्गत पात्र सेवा यात्रिविधियों में सम्मिलित हो, अभिप्रेत है;

(८) "स्टाम्प अधिभार" से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन देय स्टाम्प अधिभार के रूप में परिभाषित अधिभार अभिप्रेत है;

(९) "राज्य वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)" से उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या-८ वर्ष, 2017) की धारा ९ के अधीन उद्यग्रहीत राज्य वस्तु और सेवा कर अभिप्रेत है;

(१०) "राज्य स्तरीय समिति" से उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (जिसे यहाँ आगे एकल खिडकी अधिनियम कहा गया है), की धारा ३ की उपधारा (१) के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित सम्बन्धित नियमों अथवा नीति के अधीन लाभ की स्वीकृति के लिए समय-समय पर यथाविहित कोई अन्य समिति के रूप में यथाविहित राज्य स्तरीय समिति अभिप्रेत है।

(११) "पर्याप्त विस्तार" से क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण तथा अभिनवीकरण के प्रयोजन के लिए मौजूदा औद्योगिक इकाई/परियोजना की भूमि, भवन तथा संयंत्र एवं मशीनरी / उपस्कर्ता में, लार्ज, मेगा, अल्ट्रा मेगा तथा सुपर अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं के लिए निर्धारित न्यूनतम अबल पूँजी निवेश की सीमा, यथा: रु. ५० करोड़, रु. ७५ करोड़, रु. २०० करोड़ तथा रु. ४०० करोड़ या उससे अधिक स्थिर पूँजी निवेश की अवधिवृद्धि अभिप्रेत है;

(१२) "सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "सुपर अल्ट्रा मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्कर्ता में रु. ४०० करोड़ से रु. ४०० करोड़ तक का स्थिर पूँजी निवेश किया गया हो;

(१३) "अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट" अथवा "अल्ट्रा मेगा इकाई" से ऐसी नयी अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण की इकाई अभिप्रेत है, जिसके द्वारा भूमि, भवन तथा प्लाण्ट व मशीनरी या उपस्कर्ता में रु. २०० करोड़ से रु. ४०० करोड़ तक का स्थिर पूँजी निवेश किया गया हो;

३. पात्रता मानदण्ड (१) इस दिशा-निर्देश के पैरा-२(ज) में चिह्नित नई औद्योगिक इकाइयों/यात्रिविधियों या मौजूदा इकाइयों/यात्रिविधियों, जो निर्दिष्ट/परिभाषित क्षेत्र/आस्थान/भूमि में स्थापित हों अथवा पर्याप्त विस्तारीकरण कर रही हैं, इस नीति के अध्याधीन रहेंगी।

(२) केवल नीति के अन्तर्गत चिह्नित वह नई औद्योगिक इकाई/परियोजना/सेवा उद्यम या मौजूदा इकाई, जो इकाई की स्थापना/विस्तारीकरण के लिए पचास करोड़ रु० से अधिक का पूँजी

निवेश कर रही हैं, इस नीति के अन्तर्गत आक्षादित रहेंगी और भेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट नीति 2021 में प्रदान किए गए कितीय प्रोत्साहनों और रियायतों का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।

(८) अचल पूजी निवेश की गणना के लिए नई परियोजना/इकाई के मामले में अचल पूजी परिसंपत्ति के अलावा भूमि का मूल्य और भूमि विकास लागत (जैसा कि वास्तव में भुगतान किया गया / भुगतान किया जाना आवश्यक है) को जोड़ा जा सकता है जो प्रत्येक ३० करोड़ रुपये के पूजी निवेश के लिए १० एकड़ भूमि की अधिकतम सीमा के अधीन है।

(९) मौजूदा इकाई के विस्तार के मामले में गणना में केवल अतिरिक्त पूजी निवेश (भूमि भवन और संयंत्र और मशीनरी) को ध्यान में रखा जाएगा भौजूद इकाई के विस्तारित हिस्से के लिए इस नीति के अन्तर्गत सभी लाभ प्रोत्साहन रियायतें मौजूदा इकाई के विस्तार के प्रत्येक चरण पर लागू होंगे। इस नीति की वैधता अवधि के दौरान संबंधित विस्तारित चरणों के पहले वाणिजिक उत्पादन की तारीख से लाभ प्रोत्साहन और रियायतों पर विचार किया जाएगा।

(१०) पूजी निवेश की गणना में भूमि, भवन, नए संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, घटक मोल्ड, डाई, जिग्स और वास्तविक सम्पत्ति (उपभोज्य, डिस्पोजेबल या राजस्व प्रभार्य वस्तुओं को छोड़कर) इकाई में किया जाने वाला अचल निवेश शामिल होगा जो मूल रूप से इकाई के स्थालन के लिए आवश्यक है।

(११) संयंत्र और मशीनरी से स्थल पर स्थापित नए खरीदे गये औद्योगिक संयंत्र और मशीनरी अभियेत है तथा इसमें अन्यत्र से विस्थापित/रिसाइकिल/रिफरबिश्ड संयंत्र और मशीनरी सम्मिलित नहीं हैं।

(१२) राज्य/केन्द्रीय सरकार/विदेशी अमिकरण के अधीन किसी विभाग/अभिकरण से ऐसी इकाईया जो पूर्व से ही अनुदान/प्रोत्साहन प्राप्त कर रहे हैं इस नीति के अधीन सभान प्रकृति के प्रोत्साहन को पाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

4. पात्रता प्रमाण पत्र (१) पात्रता प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा इसे सक्षम प्राधिकारी की सत्तुष्टि तथा यह सुनिश्चित करने के पश्चात जारी किया जायेगा कि इकाई पात्रता के लिए सभी मानदण्ड पूरा करती है,

(२) नीति के अन्तर्गत चिन्हित औद्योगिक इकाई/उद्यम वाणिजिक उत्पादन के प्रारम्भ करने के दिनांक से ३० दिन के भीतर विहित प्रारूप पर वाचित दस्तावेजों/अभिलेखों सहित ऑनलाइन नामित नोडल अभिकरण के प्राधिकृत अधिकारी को पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी।

(३) पात्रता प्रमाण पत्र हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को ऑनलाइन विहित आवेदन पत्र के प्रारूप पर आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र की मुद्रित तीन प्रतियाँ अपेक्षित अभिलेखों सहित नोडल अभिकरण को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए प्रस्तुत की जायेंगी।

(४) नोडल एजेसी या उसके अधिकृत प्रतिनिधि शुल्क में आवेदन पत्र की

જાચ કરેંગે કि આવેદન પત્ર ટીક સે ભરા ગયા હૈ ઔર કયા આવશ્યક રિકોર્ડ આદિ આવેદન કે સાથ સંલગ્ન કિએ ગએ હું તથા ઇસ ઉદ્દેશ્ય કે લિએ બનાએ ગએ પણિકા મેં ઇસે રૂર્જ કરેંગે। રસ્કે બાબ આવેદન પત્ર આવેદન કી જાચ/પરીક્ષા કે લિએ વિતરણ એજેસી સિલ્કુલ કો અપ્રેશિત કિયા જાએગા। સવિતરણ એજેસી સિલ્કુલ મુખ્ય રૂપ સે આવેદન ઔર રસ્કે રિકોર્ડ કી જાંચ કરેંગી ઔર જાચ કે બાબ આવેદન કો સવીક્ષા સમિતિ કે સમક્ષ અતિમ સિફારિશ કે લિએ પ્રસ્તુત કિયા જાએગા। અપૂર્ણ/અપાન્ત્ર આવેદનોં કો કારણો સહિત સબધિત ઇકાઈ કો વાપસ કર દિયા જાએગા।

- (બ) સવીક્ષા સમિતિ આવેદન કા પરીક્ષણ કરેંગી ઔર રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ કે સાક્ષ રહે જાને કે લિએ નોંઢલ અમિકરણ કો અધિની સસ્તુતિ કે સાથ 30 દિન કે ભીતર વાપસ કરેંગી;
- (ચ) નોંઢલ અમિકરણ સવીક્ષા સમિતિ કી સસ્તુતિ કે સાથ આવેદન પત્ર કી પ્રાપ્તિ કે ક્રમ મેં આને વાહી બૈઠક મેં રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ કે સમક્ષ આવેદન કો રહેંગી। રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ સે પાત્રતા પ્રમાણ પત્ર કે આવેદન પર અનુમોદન પ્રાપ્ત હોને કે ઉપરાન્ત નોંઢલ અમિકરણ કા પ્રાધ્યકૃત અધિકારી એક સપ્તાહ કે ભીતર વિહિત પ્રારૂપ મેં પાત્રતા પ્રમાણ પત્ર જારી કરેંગા;
- (દ) મૌજૂદા ઇકાઈયોં કે વિરતાર કે મામલો મેં વિસ્તારીકરણ સે પૂર્વ ઉત્પાદન પ્રાસ્થ કરને કી તારીખ, પૂર્જી નિવેશ, રોજગાર તથા ઉત્પાદિત ઉત્પાદ/પ્રદત્ત સેવા કા વિવરણ (ઉત્પાદન ક્ષમતા સહિત) વિરતાર કે પશ્ચાત હોને વાલે પૂર્જી નિવેશ, રોજગાર સૂજન, પ્રસ્તાવિત ઉત્પાદ/સેવા (ઉત્પાદન ક્ષમતા સહિત), ઉદ્યમ રજિસ્ટ્રેશન અથવા આર્બિએમ પાર્ટ-બી તથા પાર્ટ-૧ કી પ્રત્યારી આવેદન પત્ર કે સાથ પ્રસ્તુત કરેંગી।
- (એ) વિસ્તારીકરણ કે અધીન વિદ્યમાન ઇકાઈ કે મામલે મેં પાત્રતા પ્રમાણ જત્ર આવેદન પ્રારૂપ કે સાથ ચાર્ટડ ઇંઝીનીયર/ચાર્ટડ એકાઉન્ટાન્ટ દ્વારા સમ્યક રૂપ સે પ્રમાણિત એલાઇટ વ મશીનરી/ઉપસ્કર તથા ભવન કે આંકલન તથા પૂર્જી નિવેશ કા પ્રમાણ પત્ર પ્રસ્તુત કિયા જાયેગા। વિસ્તારીકરણ કે લિએ ઇકાઈ કે પૂર્જી નિવેશ કા આંકલન વિસ્તારીકરણ કે પશ્ચાત પ્રસ્તાવિત ઉત્પાદ કે વાણિજ્યિક ઉત્પાદન/પ્રદત્ત સેવા કે પ્રાચાલન કી તારીખ તક કિયે ગયે પૂર્જી નિવેશ કે આધાર પર આકલિત કિયા જાયેગા
- (એચ) પાત્રતા પ્રમાણ પત્ર કે આવેદન કે પ્રસ્તુતીકરણ મેં દુએ વિલમ્બ કો ગુણ દોષ કે આધાર પર રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ સર્વીસ કરને કી અનુમતિ દે સકેંગી
- (ઝ) જબ તક રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ કિસી દાદે કો અનુમાદિત કરને, નીતિ કે અધીન કિસી પ્રોત્સાહન કે લિએ કોઈ અધિકાર યા દાદે કી સ્વીકૃતિ કી અનુશસા નહીં કરતી, તબ તક યહ નહીં સમજા જાયેગા કે ઇકાઈ નીતિ કી શર્તો કો પૂર્ણ કરતી હૈ
- (ઝી) સમ્વન્દ્રિત ક્રિયાન્વયન અમિકરણ દ્વારા નીતિ કે અધીન જારી કિએ ગયે પાત્રતા પ્રમાણ પત્ર કે બિના નીતિ કે અંતર્ગત કિસી પ્રોત્સાહન કે લિએ કોઈ દાદા નહીં કિયા જા સકેંગા ઔર સંકામ પ્રાધિકારી કી સત્તુષ્ટિ કે

लिए पात्रता प्रमाण पत्र की वास्तविक शर्तों का अनुपालन इकाई को करना होगा।

- (३) क्रियान्वयन अभिकरण के विषय ऐसे निर्देशों के अधीन जैसा सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये जायें, के अध्यधीन अंतिम और बाध्यकारी होंगे।
- (४) पात्रता प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के पश्चात् नीति के अधीन कोई इकाई सभी प्रकार के रियायतों, प्रात्साहनों, सहायकी (सब्सिडी), प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए अहं हो जायेगे।

5. अनंतिम पात्रता प्रमाण (३)
पत्र (पीईसी)

अनंतिम पात्रता प्रमाण ऐसा प्रमाण पत्र है, जिसे इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई इकाई की स्थापना अथवा मौजूदा इकाई के विस्तारीकरण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा प्रयोग करने से पूर्व सिडकुल से भूमि वरों में छूट/रियायत तथा लीज अथवा क्रय की गयी भूमि के निवन्धन में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क प्रभार की प्रतिपूर्ति का दावा करना हो।

- (३) मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इंडेस्ट्रियल नीति 2021 के अधीन अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित इकाई विहित प्रारूप पर अपेक्षित अभिलेखों तथा प्रमाण पत्रों के साथ नोडल अभिकरण को एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत नई परियोजना की स्थापना/मौजूदा परियोजना के विस्तारीकरण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- (४) अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के बाद आवेदन पत्र की मुद्रित/कागजी तीन प्रतिया अपेक्षित अभिलेखों सहित 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित नोडल अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
- (५) नोडल अभिकरण अथवा उसका प्रधिकृत प्रतिनिधि प्राप्तिकरण रूप से आवेदन पत्र को जांच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और सम्बन्धित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की जायेगी। नोडल अभिकरण आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति की संवीक्षा हेतु सिडकुल को अग्रसारित करेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को काशणी सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (६) संवीक्षा समिति आवेदन का घोषण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी।
- (७) नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र की प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी, राज्य स्तरीय समिति से पात्रता प्रमाण पत्र के आवेदन पर अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त नोडल अभिकरण का प्रधिकृत अधिकारी एक सप्ताह के भीतर विहित प्रारूप में अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(अ) अनंतिम पात्रता प्रभाण पत्र प्राप्त करने के बाद, नीति के अन्तर्गत एक इकाई भूमि दरों में सिड्कुल को रियायत/छूट के लिए आवेदन करने तथा रुटाप्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पत्र होगी।

(ब) नई इकाई की स्थापना या मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए आईईएम पार्ट-ए की पावती सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा उद्योग संबंधन एवं आतंरिक व्यापार विभाग (औद्योगिक सहायता संविवालय) भारत सरकार या सिंगल दिल्ली रिस्ट्रम के तहत सक्षम प्राधिकारी से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है।

6. सिविल कार्यों और संयत्र तथा मशीनरी के अर्ह/अनर्ह सामग्री (क) अर्ह सिविल कार्य:- विनिर्माण प्रक्रिया/सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुड़े निम्नलिखित सिविल कार्य अर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अर्ह माने जायेंगे:-

- विनिर्माण और आवश्यक सहायक प्रक्रियाओं में सीधे सम्बद्ध उपयोगिता क्षेत्रों सहित कारखाना शेड/भवन अर्थात् संयत्र भण्डार, गुणवत्ता नियन्त्रण, विद्युत कक्ष, अनुरक्षण कार्यशाला (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित दरें, जो भी कम हो)।
- प्रभावी एसआईडीए मानक के अनुसार आवश्यक आवासीय सुविधाएं जो लागू हो
- कारखाना परिसर पर कच्चे माल और टैंकर उत्पाद के गोदाम का निर्माण (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित प्रगती दरें, जो भी कम हो)
- आवश्यक सिविल सनिर्माण कार्य जैसे मशीन, उपरकर (वास्तविक अथवा लोक निर्माण विभाग अनुसूची की प्रभावी दरें जो भी कम हो)
- अभियान एवं पत्र विभिन्न भाष्य में प्रस्तुत नियम
- सिविल कार्यों की वास्तविक लागत विहित प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) अनर्ह सिविल कार्य: विनिर्माण प्रक्रिया/सेवाएं उपलब्ध कराने से सीधे जुड़े निम्नलिखित सिविल कार्य अनर्ह सिविल कार्य के रूप में विचार के लिए अनर्ह माने जायेंगे (सूची सम्पूर्ण नहीं है)-

- यातायारी तथा गेट।
- पहुंच सड़क/आतंरिक सड़क
- कार्यालय भवन/कार्यालय हेतु उपयोग क्षेत्र।
- कारखाने से अलग स्थान पर कच्चा माल/तैयार माल के भण्डारण हेतु निर्मित गोदाम
- कोई आवासीय भवन या रेस्ट हाउस/मेस्ट हाउस
- जलपान गृह।
- श्रमिक विश्राम गृह तथा श्रमिकों हेतु आवास

(viii) सुरक्षा/गार्ड के कमरे या बांदा।

(ix) निर्माण पुल का भार

(x) परामर्श शुल्क, करें इत्यादि।

(xi) पात्र संयंत्र तथा मशीनरी:

- सीधे निर्माण प्रक्रिया से जुड़े मशीनरी/उपकरणों का प्रारम्भिक मूल्य
- सीधे निर्माण प्रक्रिया से जुड़े उपकरण की तरह सहायक उपकरण, जिन्स छाइजा, स्टेल्लस
- संयंत्र और मशीनरी सहित जुड़ी बोटरें
- मशीनरी/उपकरणों की स्थापना निर्माण तथा कमीशन
- परिवहन शुल्क, परिवर्तन बीमा बैट/सीएसटी, उत्पादन शुल्क, प्रवेश पर कर आदि (स्वदेशी मशीनरी और उपकरणों के मामले में) का भुगतान
- आयात शुल्क, शिपिंग शुल्क, सीबीडी कंटेनर हैंडलिंग शुल्क सीमा शुल्क, निकासी शुल्क, बैट/सीएसटी भुगतान बंदरगाह से परिवहन शुल्क प्रवेश कर (आयातित मशीनरी/उपकरण के मामले में) आदि,
- गुणवत्ता नियन्त्रण, प्रदूषण नियन्त्रण और अग्निशमन उपकरण।
- आंतरिक विद्युतीकरण, पैनल बोर्ड, समर्पित ट्रांसफार्मर, गैस उत्पादक संयंत्र, विद्युत उत्पादन सेट आदि सहित विद्युत प्रतिष्ठान
- उपयुक्त सभी समग्रियों का भुगतान चैक/मांग फ़ाफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा किया जायेगा जो पात्रा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले बैंक विवरण में दर्शित होना चाहिए।
- विनिर्माण क्षेत्र में उत्थापन एवं स्थापना (Erection and Installation) सम्बन्धी प्रभारों का वास्तविक आधार पर किया गया भुगतान।
- चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना।

(xii) अनर्ह संयंत्र और मशीनरी:

- संयंत्र और मशीनरी सीधे निर्माण की प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं है।
- ईंधन उपभोज्य, पुर्जे तथा स्टोर
- कम्प्यूटर और कार्यालय कर्नीचर
- वाहन।
- सेकण्ड हैंड/पुरानी मशीनरी।

(v) સુરક્ષા પ્રણાલી સે સમ્વન્ધિત ઉપકરણ બંદ કિયે સર્કિટ ઔર સીસીટીવી કેસરે,

(vi) સ્ટેશનરી સામગ્રી।

7. અન્ય (k) પૂજી નિવેશ કા વિનિર્ધારણ પૂજી નિવેશ કે વિનિર્ધારણ મેં ઉત્પન્ન કિસી ભિન્નતા કે મામલે મેં રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ/અનુમાદને પ્રાધિકારી પરીક્ષણ કરેગા ઔર હસ પર નિર્ણય લેગા।

(l) વિસ્તારીકરણ કે અધીન વિદ્યમાન ઇકાઈ કે મામલે મેં યાત્રા પ્રમાણ પત્ર આવેદન પ્રારૂપ કે સાથ ચાર્ટેખ ઇંજીનિયર/ધાર્ટર એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા સમ્યક રૂપ સે પ્રમાણિત લાણ્ટ વ મશીનરી/ઉપસ્કરં તથા ભવન કે આકલન તથા પૂજી નિવેશ કા પ્રમાણ પત્ર પ્રસ્તુત કિયા જાયેગા, વિસ્તારિત પ્રયોજન કે લિએ ઇકાઈ કે પૂજી નિવેશ કા આકલન વિસ્તારીકરણ કે પશ્ચાત પ્રસ્તાવિત ઉત્પાદ કે વાળિઝિક ઉત્પાદન/પ્રદત્ત સેવા કે પ્રચાલન કી તારીખ તક કિયે ગયે પૂજી નિવેશ કે આધાર પર આકલિત કિયા જાયેગા

(m) નીતિ કે અધીન લાભ/ રિયાયત /પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત કરને વાલી નહી ઇકાઈયા તથા મૈઝૂદા વિસ્તારીકરણ કરને વાલી ઇકાઈયા વાળિઝિક ઉત્પાદન પ્રારૂપ કરને/સેવા કે પ્રચાલન કે છા: માહ કે પશ્ચાત નીતિ મેં પ્રદત્ત રિયાયતો/વિત્તીય પ્રોત્સાહનો કે લિએ આવેદન હેતુ અહી હોગે।

(n) સિવિલ સન્નિર્ણણ કે સાથ-સાથ સંયંત્ર ઔર મશીનોં મેં નિવેશ કી અંતિમ તારીખ, એકલ ખિડકી વ્યવસ્થા કે અન્તાગત સેદ્વાન્નિક સ્વીકૃતિ પ્રાપ્ત હોને કી તારીખ સે ઉદ્યમ રજિસ્ટ્રેશન/આઈએમ-પાટ્ટ-ની મેં વર્જ વાળિઝિક ઉત્પાદન પ્રારૂપ કરને/સેવા પ્રચાલન કી અકિત તિથિ તક હોગી

(o) સદિતરણ અધીકરણ યહ સુનિશ્ચિત કરેગા કી ઉપલબ્ધતા ઔર સરકાર દ્વારા સ્વીકૃતિ નિધિ કે આધટન કે અધ્યધીન રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ દ્વારા પ્રોત્સાહન, રિયાયત લાભ, પ્રતિપૂર્તિ કે સાપેક્ષ નિધિ જારી કી જા રહી હૈ।

(p) રાજ્ય સ્તરીય સમિતિ કિસી આવેદન પત્ર કે ઉસક દાવે/ સશોધિત દાવે પર સંદીક્ષણ સમિતિ કી સસ્તુતિ કે આધાર પર અથવા અન્ય કત્તિપથ વૈધ આધાર પર અનુમોદિત કરને યા ઉસે અસ્વીકાર કરને અથવા કોઈ આવેદન પત્ર/દાવો કો ઇસ પ્રયોજન કે લિએ જોસા કી વહ ઠીક સમજો પર્યાપ્ત નિધિ કી અનુપલબ્ધતા કે ફલરવારૂપ લબિત રહ્ય સકેગા।

(q) યદિ ઇસ બાત કી પુષ્ટિ હો કી કિસી ઔદ્યોગિક ઇકાઈ ને જાતી સૂચના દેકર ધોખે સે ઇસ નીતિ મેં પ્રદત્ત વિત્તીય પ્રોત્સાહન પ્રાપ્ત કરને કા પ્રયાસ કિયા હૈ અથવા યદિ યદિ યદિ ઇકાઈ વાળિઝિક ઉત્પાદન/સેવા પ્રચાલન કે બાદ ૫ વર્ષ કે ભીતર ઉત્પાદન બન્દ કર દેતી હૈ તો ઉસ ઇકાઈ કો સુનવાઈ કા અવસર પ્રદાન કરને કે બાદ ઐસી ઇકાઈ કો અનુદાન અથવા પ્રદત્ત વિત્તીય સહાયતા લૌટાને કે લિએ કહ સકતો હૈ, યદિ અનુદાન/પ્રતિપૂર્તિ સહાયતા ડિજિટલ મુગતાન કે જરિએ જારી કી જાયેની તથા સિલ્કુલ લાભાર્થી ઔદ્યોગિક ઇકાઈયા સે ઇસ સમ્વન્ધ મેં એક શાફ્થપત્ર લે સકતા હૈ। સ્કીમ કી સમી આપેક્ષાઓં કો પૂરા કરને

वाली लाभार्थी इकाई को वितरण से पूर्य औद्योगिक इकाई और सवितरण अभिकरण जिलकुल के बीच एक अनुबन्ध पत्र भी निष्पादित किया जायेगा।

(३) सम्बन्धित प्राधिकारी इकाई द्वारा त्रुटि से उपभोग किए गये लाभों को 30 दिन की अवधि के भीतर वापस करने के लिए कह सकेगा। यदि इकाई ऐसा करने में असफल रहती है तो प्राधिकारी धनराशि के साथ-साथ उस पर व्याज और विधि की अधीन यथा अनुमोदित ऐसे दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ वसूली हतु सक्षम विधि के न्यायालय में विधिक कार्यवाही कर सकेगा।

(४) भूमि के आवटन अथवा अनतिम पात्रता प्रमाण पत्र अथवा पावता प्रमाण पत्र की जारी करने की तारीख जो भी पहले हो, से तीन वर्ष की अवधि के भीतर यदि कोई इकाई वाणिज्यिक उत्पादन करने में असफल रहती है तो नीति के अंतर्गत दिये गये लाभों को वापस लिया जा सकेगा। वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से यदि कोई इकाई लगातार तीन वर्षों के उत्पादन के बाद बंद हो जाती है तो सम्बन्धित समिति द्वारा इस प्रकार अनुमोदित अनुदान/समिकाई की धनराशि सम्बन्धित इकाई को उनके बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से जारी कर दी जायेगी।

(५) रासी पत्र इकाईयां विहित प्रारूप के अनुसार यह विवरण देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेगी कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत सूचनाएं सही हैं।

8. उपांतरण / संशोधन इत्यादि की शक्ति (३) राज्य सरकार को किसी भी समय लोक हित में दिशानिर्देशों के किसी भाग में कोई विस्तार उपांतरण या निरसन करने का अधिकार होगा।

(४) राज्य सरकार समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इस नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नहीं होने के संबंध में रियात दे सकेगी।

(५) राज्य सरकार यदि वह ऐसा धाहे तो समुचित मामलों में सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात नीति के अधीन किसी प्रोत्साहन/लाभ को उपांतरित करने या कोई शर्त विस्तारित करने या अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगी।

9. विविध (३) यदि इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित होगा तो औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन इस संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत होगा।

(४) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन किसी मामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वचन करने की अधिकारिता होगी।

10. त्रुटियों का सुधार नीति के अधीन अनुदान की धनराशि के प्रशमन में अभिलेखों पर दर्शित किसी त्रुटि को ठीक करने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश से ऐसी इकाई को अनुदान वितरित कर सकेगी और अधिक भुगतान की वसूली यदि कोई हो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वसूल कर सकेगी। इस योजना के अधीन दिये गये लाभ वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि के पश्चात जहाँ घूर्ण रूप से लाभों का उपभोग

किया जा चुका हो, के लिए ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जायेगा।

11. अपील (क) राज्य स्तरीय समिति को सम्बन्धित विभाग/क्रियान्वयन अभिकरण/संवितरण अभिकरण के सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध किसी अपील को सुनने और उसके निस्तारण की शक्ति होगी।

(ख) राज्य स्तरीय समिति के किसी आदेश/निर्णय के विरुद्ध कोई अपील राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(ग) अपील के लिए आवेदन पत्र निर्णय को सूचित करने की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर की जा सकेगी।

12. स्पष्टीकरण/संशोधन/शोधन जारी करने का प्राधिकरण (क) उत्तराखण्ड सरकार में लोक हित में जब और जैसा आवश्यक हो नीति को संशोधित/उपात्तरित/स्पष्टता करने का अधिकार होगा यद्यपि इस नीति से सलगन प्रारूप नीति के क्रियान्वयन में सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जब और जैसे आवश्यक हों औद्योगिक विकास विभाग द्वारा उपात्तरित, परिवर्तित, विस्तारित अथवा निरसित किए जा सकेंगे।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार के औद्योगिक विकास विभाग में किसी नामले में कोई अस्पष्टता हो तो वह किसी उपबंध का सही रूप में निर्वधन करने की अधिकारिता होगी।

(ग) राज्य सरकार समुचित नामलों में सावधानीपूर्वक लाभ और हानि पर विचार करते हुए इस नीति के किसी विशेष उपबंध के लागू होने और लागू नहीं होने के संबंध में रियायत दे सकेगी।

(घ) औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के पास इन दिशानिर्देशों/नियमों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भांगे जाने पर आवश्यक स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा।

(ङ) औद्योगिक विकास विभाग को किसी भी अस्पष्टता की स्थिति में इन दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान की सही व्याख्या करने का अधिकार होगा।

अध्याय-दो

पात्र इकाईयों को लाभ/रियायतें/प्रोत्साहन

13. सिड्कुल द्वारा भूमि का आवटन

(क) इन उपबंधों के अधीन भूमि का आवटन एक्लिक आयेदकों को समय-समय पर अधिनिश्चित दिशानिर्देशों तथा सिड्कुल के प्रभावी दरों के अनुसार एकल खिड़की व्यवस्था के अधीन सिड्कुल द्वारा किया जायेगा।

(ख) इस नीति के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि आवटन में सिड्कुल के प्रभावी दरों पर लार्ज प्रोजेक्ट हेतु 15 प्रतिशत, मेंगा प्रोजेक्ट्स हेतु 25 प्रतिशत तथा अल्ट्रा मेंगा व सुपर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स हेतु 30 प्रतिशत की विशेष छूट/रियायत दी जायेगी।

(ग) इस नीति के अधीन सिड्कुल द्वारा आवटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत भूमि के आवटन के समय भुगतान किया जायेगा तथा शेष धनराशि 5 वर्ष की सभान किरतों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगी।

14. पात्र लार्ज/मेंगा/अल्ट्रा मेंगा/सुपर अल्ट्रा मेंगा परियोजनाओं के लिए नीति के अधीन प्रोत्साहन और अन्य रियायतें

(i) पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के दिनांक से आगामी पाँच वर्ष तक साधित ऋण पर सात प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज मेंगा अल्ट्रा मेंगा व सुपर अल्ट्रा मेंगा परियोजनाओं के लिए क्रमशः रु. 25 लाख, रु. 35 लाख, रु. 50 लाख व रु. 75 लाख होगी।

(ii) तैयार माल की बी2सी बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा/मात्रा निम्नानुसार होगी: -

(क) लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से आगामी 5 वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की अन्वर ग्राहक (बी. दू. सी) को विक्रय किया गया हो, का 30 प्रतिशत।

(ख) मेंगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम 6 वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एसजीएसटी कर देयता, जो राज्य के अन्वर ग्राहक (बी. दू. सी) को विक्रय किया गया हो, का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति

स्पष्टीकरण:

(i) माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है, से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि शजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अश अपने पास नहीं रखा जायेगा। वाखिल विवरणी के अनुसार एवं आईटीसी० के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे एस जी.एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की

जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी.) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

(i) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमन्य होगा।

(ii) पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी ५ वर्ष तक देय विद्युत बिल में रु 100 प्रति यूनिट की दर से अधिकतम नियत सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता अनुमन्य होगी। विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 50 लाख प्रतिवर्ष, मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. 75 लाख प्रतिवर्ष, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु 1 करोड़ प्रतिवर्ष तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु 150 करोड़ प्रतिवर्ष होगी,

स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिह्नित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप-वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को विद्युत बिल में देय प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) पात्र उद्यमों को उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से आगामी ५ वर्ष तक उत्पादन कार्य में उपभोग किये गये विद्युत बिल पर देय/भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी की पात्र उद्यमों को शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।
स्पष्टीकरण: नीति के अन्तर्गत चिह्नित पात्र सेवा गतिविधियों में सम्मिलित यथा: होटल, रिसॉर्ट, रोप-वे, मोटेल, हॉस्पिटल आदि को भुगतान की गयी इलेक्ट्रिक ड्यूटी पर प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) भूमि क्रय विलेख पत्र तथा लीज डील के निष्पदन में देय स्थान्य शुल्क प्रभार पर 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

(v) भूमि के विक्रय विलेख पत्र तथा लीज डील के पंजीयन से देय प्रति रु. 1000 पंजीकरण शुल्क के सापेक्ष रु. 999 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(vi) ईटीपी संयन्त्र की स्थापना पर 30 प्रतिशत, अधिकतम रूपया 50 लाख तक का पूंजीगत उपादान देय होगा।

(vii) बृहत रोजगार सूजन को प्रोत्साहित करने हेतु (पै-रैल सहायता) (Payroll assistance): (पै-रैल सहायता) (Payroll assistance) की अनुमन्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50. मेगा प्रोजेक्ट के लिए 100 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की अनुनतम निर्दिष्ट सीमा होगी। जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कार्यरत होंगे, को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचारियों पर रु. 500/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी ५ वर्ष तक उपादान के रूप में पै-रैल असिस्टेंस सहायता दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु पै-रैल असिस्टेंस सहायता रु. 700/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

अध्याय-तीन

लाभों के उपबन्ध, प्रक्रियाएं और संवितरण

15. ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता:

(i) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के लिए उपबन्ध।

(ii) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/लाभ के अधीन कोई समान लाभ अथवा प्रोत्साहन अथवा सहायती (समिली) प्राप्त कर रही इकाईया इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगी।

(iii) ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वित्तीय बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के लिए लिए गए सावधि ऋण पर स्वीकार्य होगी। नीति के लागू होने से पूर्व लिया गया कोई भी सावधि ऋण जिसकी पहली किश्त इस नीति के लागू होने से पूर्व संवितरित की जा चुकी हो पर ब्याज प्रोत्साहन प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ अनुमय नहीं होगा।

(iv) ब्याज प्रतिपूर्ति सह यता पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऋण के पुनः गुणतान की अवधि तक जो भी पहले हो अनुज्ञेय होगी। ब्याज प्रतिपूर्ति सह यता की अवधि प्रथम किश्त के संवितरण की तारीख से अनुज्ञेय अवधि तक गणना में ली जायेगी।

(v) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता ऐसे इकाईयों को दी जायेगी जिन्होंने नियमित रूप से वित्तीय संस्थाओं/बैंक को किश्त और ब्याज का भुगतान किया हो। वहि इकाईया इसमें असफल होगी तो असफलता अवधि के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता नहीं दी जायेगी और उपर्युक्त उपखण्ड (iii) में यथाउलिलिखित पांच वर्ष की अवधि से ऐसी असफलता अवधि घटा दी जायेगी।

(vi) ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के दावे हेतु प्रक्रिया:

(i) नीति के अधीन ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता उपभोग करने के इच्छक पात्र इकाईयों को एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत www.investitorarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप पर अपेक्षित अभिलेखों के साथ ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता का दावा प्रस्तुत करना हो। ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्था का इस आवश्य का प्रमाण पत्र कि इक ई द्वारा नियमित रूप से मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान कर रहे हैं प्रस्तुत करना होगा, बैंक मूलधन/ब्याज के पुनर्भुगत न में किसी असफलता के बारे में भी प्रमाण पत्र में उल्लेख करंगे, ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रथम आवेदन पत्र वित्तीय उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात 45 दिन के भीतर किया जायेगा तत्पश्चात के दावे त्रैम सिक आधार पर त्रैगास समिति के भाद 45 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धी नोडल अधिकारी को www.investitorarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा औनलाईन प्रस्तुतीकरण के गामते में आवेदन पत्र की मूल्दिक तीन सेट सलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अधिकरण की सम्यक हस्ताक्षरोपरात भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अधिकरण अथवा उसका ग्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जाव करेगा कि आवेदन पत्र सम्बन्धित रूप से भरा गया है और भवित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोग के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से संवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु मह प्रबन्धक सिड्कूल को अप्रसारित किया जायेगा सिड्कूल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाव/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपखण्ड (i) में यथाउपबन्धित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहा आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर अवधि किया जा सकेगा।

(iv) सवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी सस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण सवीक्षा समिति की सस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को स्थगित करेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति सवीक्षा समिति की सस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि कार्यवृत्त का विवरण रहेगा बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा सवितरण अभिकरण का प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई व्याज प्रतिपूर्ति सहायता के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(vii) व्याज प्रतिपूर्ति सहायता का सवितरण करने के लिए प्रक्रिया:

(i) व्याज प्रतिपूर्ति सहायता का सवितरण केवल वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात किया जायेगा।

(ii) नामित सवितरण अभिकरण अथवा सवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी सदस्य सचिव राज्य स्तरीय समिति से सूचना प्राप्त होने पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुगोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और स्वीकृत धनराशि त्वरित रूप से सम्बन्धित इकाई को डिसाइड ड्राफ्ट/पे आईए/ईक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

16. विद्युत सहायता/विद्युत देयक सहायकी (समिती)

(i) विद्युत सहायता के लिए उपबंध

(i) पात्र इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी पाच वर्षों के लिए यह सहायता दी जायेगी।

(ii) ल. रु. ५०,००० मेंगा अल्ट्रा मेंगा तथा सुपर अल्ट्रा मेंगा परियोजनाओं को वाणिज्यिक सत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात आगामी ५,८ वर्षों तक उत्पादन कार्य में उपभोग की गयी विद्युत के बिलों पर रु. १ प्रति यूनिट की दर से अधिकतम निर्दिष्ट सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी विद्युत प्रतिपूर्ति सह यता की अधिकतम वार्षिक सीमा लार्ज प्रोजेक्ट्स हेतु रु ५० लाख प्रतिवर्ष मेंगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु ७५ लाख प्रतिवर्ष अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु. १ करोड़ प्रतिवर्ष तथा सुपर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट्स हेतु रु १५० करोड़ प्रतिवर्ष होगी।

(iii) पात्र विनिर्माणिक इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात आगामी पाच वर्ष तक विद्युत अधिभार का शातप्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगी।

(iv) भुगतानित विद्युत अधिभार तथा उपभोग की गई विद्युत यूनिट पर एक रूपया प्रति की प्रतिपूर्ति केवल विनिर्माण/उत्पादन अथवा उससे सबधित प्रयोजनों के लिए जो कि इकाईयों को औद्योगिक प्रयोग के लिए दिये गये एकल संयोजनों पर लागू होगी।

(v) विद्युत सहायता के दावे हेतु प्रक्रिया:

(i) विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता तथा विद्युत अधिभार की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र इकाईया विहित प्रारूप पर नोडल अभिकरण के समक्ष ऑनलाइन आवेदन करेगे। पात्र इकाई वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारम्भ के पश्चात 45 दिन के भीतर अपना प्रथम दावा प्रस्तुत करेगी, तत्पश्चात ब्रैमासिक आधार पर ब्रैमास समाप्ति के उपरान्त 45 दिन के भीतर दावे प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा, औनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रित तीन सेट सलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरात भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जाच करेगा कि आवेदन पत्र सम्बन्धित रूप से भरा गया है और सबधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए स्खे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवीक्षा समिति के समुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक, सिडक्ल को अग्रसमरित किया जायेगा। सिडक्ल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाच/परीक्षण कर सवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हे प्रस्तुत किया जायेगा अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपर्युक्त (i) में यथाउपबन्धित समवावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम ८० दिन का विलम्ब शाय्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्जित किया जा सकेगा।

(iv) सवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ ३० दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण सवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति सवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचर कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना जिसमें बैठक की तारीख स्वीकृत धनराशि कार्यवृत्त का विवरण रहेगा, बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात, जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी। सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह रागा है कि इकाई विद्युत सहायता/विद्युत देयक सहायकी के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(vii) विद्युत सहायता से संवितरण की प्रक्रिया:

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिक श्री नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से सबधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खातों में सीधे अन्तरित करेगा।

17. स्टाम्प अधिभार

(i) स्टाम्प अधिभार छूट/प्रतिपूर्ति के लिए सुधारणा।

पत्र इकाईयों को भूमि क्रय/भूमि पट्टे के निष्पादन पर स्टाम्प अधिभार के भुगतान की ५० प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) स्टाम्प अधिभार छूट के लिए प्रक्रिया:

(i) इस नीति के अधीन विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण के लिए अथवा नई इकाई के स्थापना के लिए पात्र इकाईया विहित प्रारूप में “स्टाम्प अधिभार के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन” प्रारूप में सम्यक रूप से पूर्ण

भरा गया आवेदन पत्र नोडल अभिकरण को प्रस्तुत करेगा विलेख के निष्पादन के पश्चात 45 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति सहायता का दावा अनन्तिम पात्रता प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जायेगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

- (i) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा औनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रित तीन सेट सलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरांत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जाच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और सबधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से सदीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक सिडकूल को अग्रसारित किया जायेगा सिडकूल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाच/परीक्षण कर सदीक्षा समिति के सपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (ii) जहां उपलब्ध (i) में यथाउपचारित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहा आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्रधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्खित किया जा सकेगा।
- (iii) सदीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी रास्तुति के साथ 30 दिन के भीतर याप्त करेगी। नोडल अभिकरण सदीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (iv) राज्य प्राधिकृत समिति सदीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विवार कर निर्णय लागी, नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की गूच्छा जिसमें बैठक की तारीख स्वीकृत धनराशि कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होती सभी सम्बन्धित पक्षों तथा सदीक्षण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (v) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई स्टाम्प अधिभार छूट/प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं है वहा वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसार उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण, अभिलिखित करेगी समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(vi) भुगतानित स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया:

नामित सदीक्षण अभिकरण अथवा सदीक्षण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूच्ना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से सबधित इकाई को डिमाप्ड ह्राफ्ट/पे आर्डर/चैक, आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे जन्तरित करेगा।

18. निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति:

(क) निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उपबंध:

इस नीति के अधीन पात्र इकाई को क्रय विलेख पत्र/पट्टा विलेख के निबन्धन के लिए भुगतानित शुल्क के सापेक्ष प्रति रु 1000 निवासन शुल्क पर रु 999 की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी।

(v) निबन्धन शुल्क के प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रक्रिया:

(i) भुगतानित निबन्धन शुल्क की प्रतिपूर्ति उपभोग करने के इच्छुक पात्र इकाई भूमि क्रय/भूमि विलेख के निबन्धन के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि में शपथपत्र और चार्टेड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के साक्ष्य एवं भुगतानित निबन्धन शुल्क के विवरण सहित विहित प्रारूप में रजिस्ट्रीकरण शुल्क के प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र में सम्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investultarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट सलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरप्राप्त भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्रधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से अवेदन पत्र की जगह करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और सबधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा तत्परतात आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवीक्षा सामिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु भागप्रबन्धक सिडक्टल को अग्रसारित किया जायेगा। शिडक्टल के सारे सौ प्राप्त अवेदन पत्रों की जाय/परीक्षण कर सवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां के उपर्युक्त (i) में यथाउपबन्धित सम्यावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने से अधिकतम 90 दिन का वित्तम् राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमान देन पर मर्जित किया जा सकेगा।

(iv) सवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य सारीय समिति के सम्मुख रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्कृति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की समनूति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य संसदीय समिति के सामने आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति सवीक्षा समिति की समनूति द्वारा सम्मुख आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना जिसमें बैठक की तारीख स्थीकृत धनराशि कार्यवृत्त का विवरण रहेगा बैठक में लिए गये निर्णय के तृतीय प्रक्रिया जो बैठक की तारीख से सत्र दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा सावेदण अभिकरण को प्रेसित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य सारीय समिति की यह रुचि है कि इकाई रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं है वहां वह ऐसी इकाई को सन्दर्भात् का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित से अरवीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तृतीय पश्चात किन्तु राज्य सारीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय ने तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(vii) संवितरण हेतु प्रक्रिया:

नामित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोइ अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमान देत दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश प्राप्ति करेगा और त्वरित रूप से सबधित इकाई को डिमाण्ड झापट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

19. ईटीपी पर पूँजीगत उपादान:

(i) ईटीपी संयंत्र की स्थापना हेतु उपादान के लिए उपबंध:

(ii) पात्र परियोजनाओं/इकाईयों का नीति के अधीन, ईटीपी संयंत्र की स्थापना लागत पर 30 प्रतिशत अधिकतम रूपया 50 लाख की पूँजीगत उपादान सहायता दी जायेगी।

(iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/पैकेज के अधीन समान सहायकी प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूँजी सहायकी के लिए अहं नहीं होगी।

(iv) ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी ईटीपी के स्थापना से सीधे जुड़े हुए नियत पूँजी निवेश पर आगणित की जायेगी।

(v) पात्र इकाईयां ईटीपी संयंत्र के सफलतापूर्वक पूर्णता के पश्चात ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।

(vi) ईटीपी के स्थापना पर उपादान दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

(i) ईटीपी के स्थापना पर पूँजीगत उप दान प्राप्त करने की इच्छुक पात्र इकाई वाणिजिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को तथ्यों की पुष्टि में विल वार्डभर्स, भुगतान के विवरण, शपथपत्र और चार्टेंड एकाउण्टेट द्वारा सम्यक रूप से सत्यापित भुगतान के विवरण विहित न्यूलॉप में 'ईटीपी हेतु सहायकी के दावों के लिए आवेदन पत्र' में प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट सलान सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोग्राहत भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्रधिकृत प्रतिलिपि प्रारम्भिक रूप से अवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र सम्बन्धित रूप से भरा गया है और सद्वित अगिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीधता से संवीक्षा समिति के समुद्देश प्रस्तुत किये जाने हेतु भागप्रबन्धक रिडिक्युल को अग्रसारित किया जायेगा, सिडिक्युल के रत्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर संवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा। अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां ऊपर सुधारणा (i) में गथाउपचालित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्जित किया जा सकेगा।

(iv) संवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी सस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण संवीक्षा समिति की सस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की सस्तुति द्वारा सस्तुत भावेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि कार्यवृत्त का विवरण रहेगा। बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी सभी सम्बन्धित यक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई ईटीपी के स्थापना हेतु सहायकी के लिए पात्र नहीं है वहा वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्तीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई

तथा सभी सम्बन्धितों को तुरत पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(५) सवितरण हेतु प्रक्रिया:

नामित सवितरण अभिकरण अथवा सवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए अदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से सबधित इकाई को डिमाण्ड फ्राप्ट/पे आर्डर/चेक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

20. उच्च रोजगार सृजन चलन्यन के लिए पे-रौल सहायता:

(क) पे-रौल सहायता के लिए उपबंध:

(i) (पे-रौल) (Payroll assistance) सहायता की अनुमत्यता हेतु लार्ज प्रोजेक्ट के लिए 50 मेंगा प्रोजेक्ट के लिए 100 अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट के लिए 200 तथा सुधर अल्ट्रा मेंगा प्रोजेक्ट के लिए 400 लोगों को नियमित रोजगार की न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा होगी जिन उद्यमों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक नियमित कर्मचारी कावरत होंगे को निर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त नियोजित कर्मचरियों पर रु 500/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की दर से आगामी 5 वर्ष तक उपादान के रूप में पे-रौल असिस्टेस सहायता दी जायेगी, महिला कर्मचरियों हेतु यह दर रु. 700/- प्रतिमाह प्रति कर्मचारी होगी।

(ii) अतिरिक्त कर्मचारी से निर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों की सछा अभिग्रहत है

(iii) केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य योजना/पैकेज के अधीन समान राहायकी उपभोग करने वाली इकाई इस नीति के अधीन पूँजी सहायती के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv) पे-रौल सहायता के दावों के लिए प्रक्रिया

(i) पे-रौल सहायता की प्रतिपूर्ति उपगोग करने के इच्छुक पात्र इकाई निर्दिष्ट संख्य से अधिक कर्मचारियों के नियोजन के 45 दिन के भीतर नोडल अभिकरण को आवेदन पत्र तथ्यों/साक्षयों तथा श्रम विभाग द्वारा प्रभागित विवरण विहित प्रारूप में पे-रौल सहायता के दावों के लिए आवेदन पत्र में प्रस्तुत करेगा।

(ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की भुदिक तीन सेट सलगन सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरात भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जांच करेगा कि आवेदन पत्र सम्बन्धित रूप से भरा गया है और सबाधृत अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलगन किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रतिष्ठि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक सिड्कूल को अप्रसारित किया जायेगा। सिड्कूल के स्तर से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण कर सवीक्षा समिति के सपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा, अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।

(iii) जहां उपर अध्याय तीन के खण्ड 6(b)(i) में यथाउपबंधित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहा आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम 90 दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुमोदन पर मर्हित किया जा सकेगा।

(iv) सवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी सस्तुति के साथ 30 दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण सवीक्षा समिति की सस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।

(v) राज्य प्राधिकृत समिति संवीक्षा समिति की सत्तुति द्वारा सत्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना जिसमें बैठक की तारीख, स्वीकृत धनराशि, कार्यवृत्त का विवरण रहेगा बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात जो बैठक की तारीख से सात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा सवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।

(vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह सय है कि इकाई पे-सैल सहायता के लिए पात्र नहीं है वहा वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरन्त पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम सात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।

(vii) **सवितरण हेतु प्रक्रिया:**

नामित सवितरण अभिकरण अथवा सवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता के अद्यधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से संबंधित इकाई को डिमाण्ड फ्लाण्ट/पे आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अनुरित करेगा,

21. **एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति:**

(i) एसजीएसटी के लिए उपबम्बः

(ii) औद्योगिक इकाई/परियोजना अपने उद्यम को माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत करायेगी।

(iii) रजनीर्भित माल/यस्तु के बीदूसी विक्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के समायोजन के पश्चात देय कुल शुद्ध एस जी एस टी की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एवं मात्रा निम्नानुसार होगी:-

(a) लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से आगामी ५ वर्ष हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस जी एस टी कर देयता, जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू. सी) को विक्रय किया गया हो, का ३० प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

(b) मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स/सुपर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिये उत्पादन तिथि से अग्रिम ५ वर्षों हेतु इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजन के पश्चात कुल शुद्ध एस जी एस टी कर देयता जो राज्य के अन्दर ग्राहक (बी. टू. सी) को विक्रय किया गया हो, का ५० प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

स्पष्टीकरण:

(i) माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में जमा की जायेगी तथा कोई भी अश अपने पास नहीं रखा जायेगा दाखिल विवरणी के अनुसार एवं आई०टी०सी० के सम योजन के पश्चात कुल कर दायित्व की देखते हुए इकाई को इस योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किये गये माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के अन्तर्गत दिए गए ऐसे रस.जी एस.टी. कर के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (बी.टू.सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

(ii) एसजीएसटी प्रतिपूर्ति सहायता का लाभ केवल विनिर्माण उद्योगों को ही अनुमत्य होगा।

(iii) एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु प्रक्रिया

(iv) पत्र विनिर्माणक इकाईयों द्वारा सर्वप्रथम माल और सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसूच मासिक/त्रैमासिक विवरणी दाखिल की जायेगी तथा विवरणी के अनुसार राज्य माल और सेवा कर (SGST) अधिनियम के अन्तर्गत जो भी कर दायित्व बनता है से सम्बन्धित सम्पूर्ण धनराशि राजकोष में

जमा की जायेगी तथा काई भी अश अपने पास नहीं रखा जायेगा। दखिल विवरणी के अनुसार एवं आई०टी०सी० के समायोजन के पश्चात कुल कर दायित्व को देखते हुए इकाई को इन दिशा निर्देशों के प्राविधानों के अनुसार भुगतान किये गये राज्य माल और सेवा कर (एस०जी०एस०टी०) के अन्तर्गत दिये गये, ऐसे एस०जी०एस०टी० के भाग की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो राज्य के अन्दर सीधे ग्राहक (धी दू सी) को विक्रय से सम्बन्धित हो।

- (ii) आवेदन पत्र सम्बन्धित नोडल अधिकारी को www.investuttarakhand.com पोर्टल पर विहित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण के मामले में आवेदन पत्र की मुद्रिक तीन सेट सलग्न सभी अभिलेखों के साथ नोडल अभिकरण को सम्यक हस्ताक्षरोपरात भी प्रस्तुत किया जायेगा। नोडल अभिकरण अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रारम्भिक रूप से आवेदन पत्र की जाच करेगा कि आवेदन पत्र समुचित रूप से भरा गया है और सबधित अभिलेख इत्यादि आवेदन के साथ सलग्न किए गये हैं अथवा नहीं तथा इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि करेगा। तत्पश्चात आवेदन पत्र को शीघ्रता से सवीक्षा समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने हेतु महाप्रबन्धक शिडकुल को अग्रसरित किया जायेगा। शिडकुल के स्तर से ग्रास आवेदन पत्रों की जाच/परीक्षण कर सवीक्षा समिति के संपरीक्षण हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जायेगा अपूर्ण/अपात्र आवेदनों को कारणों सहित सम्बन्धित इकाई को वापस कर दिया जायेगा।
- (iii) जहां उपखण्ड—(i) में यथाउपचारित समयावधि के पश्चात आवेदन पत्र जमा किया जाता है वहां आवेदन के विहित तारीख से आवेदन को जमा करने में अधिकतम ३० दिन का विलम्ब राज्य प्राधिकृत समिति के अनुसेदन पर भर्तित किया जा सकेगा।
- (iv) सवीक्षा समिति आवेदन का परीक्षण करेगी और राज्य स्तरीय समिति के समक्ष रखे जाने के लिए नोडल अभिकरण को अपनी संस्तुति के साथ ३० दिन के भीतर वापस करेगी। नोडल अभिकरण सवीक्षा समिति की संस्तुति के साथ आवेदन पत्र के प्राप्ति के क्रम में आने वाली बैठक में राज्य प्राधिकृत समिति के समक्ष आवेदन को रखेगी।
- (v) राज्य प्राधिकृत समिति सवीक्षा समिति की संस्तुति द्वारा संस्तुत आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेगी। नोडल अभिकरण द्वारा राज्य प्राधिकृत समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, स्थीकृत धनराशि कार्यवृत्त का विवरण रहेगा, बैठक में लिए गये निर्णय के तुरन्त पश्चात जो बैठक की तारीख से ज्ञात दिन से अधिक नहीं होगी, सभी सम्बन्धित पक्षों तथा संवितरण अभिकरण को प्रेषित की जायेगी।
- (vi) जहां राज्य स्तरीय समिति की यह राय है कि इकाई एसजी०एसटी प्रतिपूर्ति सहायता के लिए पात्र नहीं है वह वह ऐसी इकाई को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करायेगी और लिखित में अस्वीकार करने के कारण अभिलिखित करेगी। समिति का निर्णय राज्य प्राधिकृत समिति के नोडल अभिकरण द्वारा इकाई तथा सभी सम्बन्धितों को तुरस पश्चात किन्तु राज्य स्तरीय समिति बैठक द्वारा लिये गये निर्णय की तारीख से अधिकतम ज्ञात दिन के भीतर सूचित किया जायेगा।
- (vii) संवितरण हेतु प्रक्रिया:

नाप्रित संवितरण अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी नोडल अभिकरण से सूचना की प्राप्ति पर इस प्रयोजन के लिए निधि की उपलब्धता की अधाधीन अनुमोदित दावे की धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करेगा और त्वरित रूप से सबधित इकाई को डिमाण्ड ड्राफ्ट/पै आर्डर/चैक/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाते में सीधे अन्तरित करेगा।

अध्याय चार

विभिन्न प्रोत्साहन/लाभ रियायतों के लिए आवेदन किए जाने हेतु आवेदन पत्र, प्रारूप, परिशिष्ट और संलग्नक

नीति के अधीन विभिन्न प्रोत्साहनों/लाभों/रियायतों इत्यादि के लिए आवेदन पत्र, प्रारूप, परिशिष्ट और संलग्नक निम्नवत है। ये क्रियान्वयन अभिकरण, नोडल अभिकरण अथवा संवितरण अभिकरण द्वारा समय समय पर जैसा अपेक्षित हो, यथाविहित नये प्रारूपों और ढांचों में उपांतरित अथवा परिवर्तित किये जा सकते हैं।

क्र.सं.	विवरण	प्रपत्र विवरण
1.	संवीक्षा समिति	परिशिष्ट ~ 1
2.	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (नई इकाई)	ईसी-1
3.	पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन (विद्यमान इकाई)	ईसी-1 क
4.	पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	ईसी-2
5.	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन	पीईसी-1
6.	अनंतिम पात्रता प्रमाण पत्र का प्रारूप	पीईसी-2
7.	व्याज सहायकी (सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (आईएनटी)
8.	एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (दावा)
9.	विद्युत देयक में सक्षिणी/विद्युत सहायता के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीबीआर)
10.	स्टाम्प अधिभार की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (एसटीडी)
11.	रजिस्ट्रेशन शुल्क की प्रतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन	दावा (आरजीएफ)
12.	ईटीपी की सहायकी (सब्सिडी) के दावे हेतु आवेदन	दावा (इटीपी)
13.	पै-रील सहाय के दावे हेतु आवेदन	दावा (पीआरए)
14.	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (समस्त नई इकाईयों हेतु)	अभियंता (नई इकाई)
15.	अभियंता प्रमाण पत्रों का प्रारूप (विद्यमान इकाईयों हेतु)	अभियंता (विद्यमान इकाई)
16.	सियिल कार्य की वास्तविक लागत का वक्तव्य	—
17.	संयंत्र और उपस्कर तथा अन्य सम्पत्ति पर नियेश का विवरण	—
18.	चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (नई इकाई)	सीए-1
19.	चार्टर्ड एकाउण्टेंट प्रमाण पत्र का प्रारूप (सौजूदा विद्यमान इकाई)	सीए-2
20.	शपथ पत्र का प्रारूप	शपथ पत्र
21.	उपक्रम का प्रारूप	उपक्रम

परिशिष्ट का
संवीक्षा समिति

क्र.सं.	समिति के सदस्य	पद
1.	प्रमुख सचिव / सचिव (उद्योग), उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक एवं आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड अथवा उनके प्रतिनिधि, जो निदेशक उद्योग के स्तर के हैं।	सदस्य
3.	प्रबन्ध निदेशक, सिड्कुल।	सदस्य
4.	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5.	निदेशक, वित्त / वित्त नियंत्रक, सिड्कुल	सदस्य
6.	महाप्रबन्धक, सिड्कुल।	सदस्य सचिव

आज्ञा से,
डॉ पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 675/VII-A-2/2022/17-Industry/2013, dated December 29, 2022 for general information.

Office Memorandum

December 29, 2022

No. 675/VII-A-2/2022/17-Industry/2013--In pursuance of Office Memorandum No. 1675/VII-A-2/2021/17-Industry/2013 dated 31st December 2021, Industrial Development Section-2, Government of Uttarakhand the Governor is pleased to make the following operational guidelines for the implementation of Mega Industrial and Investment Policy, 2021 to encourage the establishment of Large, Mega, Ultra Mega and Super Ultra Mega Projects and create employment opportunities in the State :--

The Mega Industrial and Investment Policy, 2021 Operational Guidelines, 2022

Chapter- One

1. **Short Title and commencement** (1) These guidelines may be called the Mega Industrial and Investment Policy Rules, 2021 Operational Guidelines, 2022 (abbreviated as MIIP Operational Guidelines 2022)

- (2) These guidelines shall be applicable from the date of issue of Mega Industrial & Investment Policy, 2021 i.e. 31st Dec, 2021 & remain in force for the entire validity period of this policy.
- (3) Eligible enterprises / units may avail the benefits, incentives & concessions as per Mega Industrial & Investment Policy, 2021 for maximum five years from the date of commencement of commercial production / service rendered within the policy validity period.

Explanation: Under the Mega Industrial & Investment Policy-2015 (as amended from time to time), the benefits of financial incentives provided in the said policy to the established / under construction new and expansion projects / units, will be permissible only as per the provisions of Mega Industrial & Investment Policy operational guidelines-2016 promulgated from Industrial Development Section-2, Government of Uttarakhand Notification No. 640/2016/VII-1/17-Udyog/2013 dated 28-07-2016.

2. Definition

- (a) **Commencement of commercial production** means
 - (i) For New Unit the date on which the unit issues the first Sale bill of the finished products.
 - (ii) For an Existing Unit making investment for expansion, the date on which the unit issues the first sale bill of the finished product after completion of expansion ;
- (b) "Competent Authority" means the officer or agency or representative of the implementing agency to whom specific authority has been entrusted under these guidelines for the implementation of this policy ;
- (c) **Disbursing Agency** means the Uttarakhand State Industrial and Infrastructure Development Corporation Limited (abbreviated to SIIDCUL) or such other agencies/departments as may be authorized from time to time to disburse sanctioned grants/financial incentives under this policy ;
- (d) "Electricity Duty" means as defined in Uttar Pradesh Power Electricity (Duty) Act, 1952 (Uttarakhand Adaptation and Modification) Order, 2001 ;
- (e) "Existing industrial unit" means an industrial unit, which is already in commercial production and services rendered before the 31st December, 2021 in the state and who has obtained in-principle approval for undergoing expansion of the existing project/unit with the approval of State/District Empowered Committee by submitting an application on Common Application Form-1 on www.investuttarakhand.com Portal ;
- (f) **Industrial Area/Estate/Special Industrial Estate** or any other notified/identified land means :
 - (i) Industrial Area / Estate developed by SIIDCUL.

- (ii) Industrial Estate developed by State Industries Department.
- (iii) Private Industrial Area / Estate / Special Industrial Estate notified by State Government from time to time.
- (iv) Any parcel of land notified and designated for the use of Industrial / Commercial , and Identified Service activities in the Zonal Master Plan of the concerned regulated Areas in the State.
- (v) Land notified and designated for the identified activities in regulated areas, the building map has been approved by the competent authority of the concerned development authority for setting up the project.
- (v) The land has been declared as non-agriculture land under section-143 of the Uttar Pradesh (Uttarakhand) Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 as amended from time to time, by the competent authority for such purpose;
- (g) "Industrial/Service Sector" Unit means any such industrial unit/project or eligible service sector enterprise which is a registered enterprise under the Goods and Services Tax Act, 2017 and for which acknowledgment has been obtained by filing IEM Part-A (Letter of Intent) in the Government of India, Department of Industry Promotion and Internal Trade (Secretariat of Industrial Assistance);
- (h) "Implementing Agency" means the Industrial Development Department of the Government of Uttarakhand or the office of the Director General and Commissioner of Industries, Uttarakhand, which has been designated as the implementing agency for the implementation of the policy ;
- (i) "Large project" or "Large unit" means a new or substantial expansion unit by which fixed capita investment of Rs 50 crore to Rs 75 crore has been made in land, building and plant and machinery or equipment ;
- (j) "Mega project" or "Mega unit" means a new or substantial expansion unit by which fixed capital investment of Rs 75 crore to Rs 200 crore has been made in land, building and plant and machinery or equipment ;
- (l) "Manufacturing Enterprise" means an industrial undertaking or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods in any manner whatsoever, which relates to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation Act, 1951) (55 of 1951) and which is defined as a manufacturing enterprise in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 ;

- (i) "New industrial unit" means the industrial unit which has been obtained In-principle Approval under Single Window Facilitation and Clearance Act, 2012 for setting up a Large, Mega, Ultra Mega and Super Ultra Mega Projects with the approval of State / District Empowered Committee by submitting Common Application Form-1 on www.investuttarakhand.com Portal ,
- (ii) "New project/unit" means the project/unit which has established and started their commercial production during the validity period of Mega Industrial and Investment Policy-2021 (MIIP-2021) ;
- (iii) "Nodal agency" means the State Udyog Mitra Cell or Single Window System Cell in Directorate of Industries, Uttarakhand which has been authorized to receive the applications, forward/submit them for scrutiny/testing and acceptance of the applications at the appropriate level under this policy. The Directorate of Industries or such other officer authorized by it shall act as the authorized officer of the nodal agency ;
- (iv) "Policy" means the Mega Industrial and Investment Policy, 2021;
- (v) "Scrutiny Committee" means the committee constituted to scrutinize the applications and claims received under the guidelines and policy as mentioned in Annexure-A to these guidelines ;
- (vi) "Service Enterprise" means an enterprise engaged in providing or rendering of services as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and such activity is included in the eligible service activities under this policy ;
- (vii) "Stamp surcharge means" a surcharge defined as the stamp surcharge payable under the Indian Stamp Act, 1899 (as in force in the State of Uttarakhand);
- (viii) "State Goods and Services Tax (CGST)" means the State Goods and Services Tax levied under section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 6 of the year, 2017);
- (ix) State Level Committee shall mean the relevant rules as amended from time to time read with sub-section (1) of section 3 of the Uttarakhand Enterprise Single Window Clearance and Facilitation Act, 2012 (hereinafter referred to as the Single Window Act) or any other committee as may be prescribed from time to time for sanction of benefits under the policy is from the State Level Committee as prescribed.
- (x) "Substantial Expansion" means the minimum fixed capital investment limit prescribed for large, mega, ultra mega and super ultra mega projects in the land, building and plant and machinery/equipment of the existing industrial unit/project for

the purpose of capacity expansion/modernization and innovation, namely Rs. 50 crore, Rs. 75 crore, Rs. 200 crore and Rs. 400 crore or more accretion of Fixed capital investment;

- (v) Super Ultra Mega Project or Super Ultra Mega Project Unit means a new or substantial expansion unit by which fixed capital investment of more than Rupees 400 crores has been made in land, building and plant and machinery or equipment,
- (w) Ultra mega project or Ultra Mega unit means a new or substantial expansion unit by which fixed capital investment of Rs 200 crore to Rs 400 crore has been made in land, building and plant and machinery or equipment;

3. Eligibility Criteria

- (a) The identified new industrial units / activities or existing units / activities which are going under expansion in the designated / defined Area / Estate / Land in Para-2(j) of this guidelines, will be covered in this Policy.
- (b) Only those new industrial unit/project/service enterprise or existing unit identified under the policy, which is investing capital of more than fifty crore rupees for the establishment/expansion of the unit, will be covered under this policy and will be eligible to avail the benefits of financial incentives and concessions provided in the Mega Industrial and Investment Policy, 2021
- (c) For calculating this amount in case of new project/unit apart from fixed capital asset the value of land and Land development cost (as actually paid / required to be paid) may be added subject to a maximum ceiling of 10 Acre of land for every Rs. 50 Crore Capital Investment.
- (d) In case of expansion of existing unit, only the additional capital investment (land, building and plant and machinery) will be taken into account for computing. All benefits, incentives, concessions under this policy for the expanded portion of the existing unit shall be applicable at each stage of expansion of the existing unit. The benefits, incentives and concessions shall be considered from the date of first commercial production of the respective extended phase/s during the validity period of this policy
- (e) Calculation of capital investment will include fixed investment in land, building, new plant and machinery, equipment, components, moulds, dies, jigs and actual assets (Except consumable, disposable or revenue chargeable items) unit which is basically required for the operation of the unit.
- (f) Plant & Machinery means newly purchased industrial plant & machinery installed at site and does not include displaced / recycled / refurbished plant & machinery from elsewhere.

4. **Eligibility Certificate**

- (g) Such units which are already receiving grants/incentives from any department / agency under the State / Central Government / foreign agency, will not be eligible for incentive of similar nature under this policy
- (a) Eligibility Certificate is a certificate which shall be issued by the competent authority in this regard. This shall be issued ensuring that all criteria for eligibility have been fulfilled to the full satisfaction of the competent authority
- (b) The industrial unit/enterprise identified under the policy shall apply online on the prescribed format along with the required documents/records to the authorized officer of the designated nodal agency for eligibility certificate within 90 days from the date of commencement of commercial production.
- (c) After applying on the prescribed format of online application form to the concerned authority for eligibility certificate, three copies of the printed application form will be submitted with requisite records countersigned to the nodal agency.
- (d) The nodal agency or its authorized representative will initially check the application form that the application form has been filled properly and whether requisite records etc have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for this purpose. After that the application form will be forwarded to the disbursing agency SJIDCL for checking/examination of the application. The disbursing agency SJIDCL will primarily scrutinize the application & its records and after examination the application will be submitted for final recommendation before the Scrutiny Committee. Incomplete, ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (e) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for being placed before the State Level Committee.
- (f) The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee. After getting approval on the application of eligibility certificate from the State Level Committee, the authorized officer of the nodal agency will issue the eligibility certificate in the prescribed format within a week.
- (g) In case of expansion of existing units, date of commencement of production before expansion, details of capital investment, employment and product produced or service rendered (including production capacity), capital investment after expansion, employment generation, proposed product/service (including production capacity) enterprise registration or IEM Part A & Part-B shall also be submitted along with the application form.

- (b) In case of existing unit under expansion, eligibility certificate will be submitted along with the application format, duly certified by the Chartered Engineer/Chartered Accountant for the assessment of plant and machinery/equipment and building and the certificate of capital investment. The capital investment of the unit for the extended purpose shall be calculated on the basis of capital investment made after expansion till the date of commercial production of the proposed product/operation of the service rendered.
- (i) The State Level Committee may allow the delay in submission of application for eligibility certificate to be condoned on the basis of merit.
- (j) Unless the State Level Committee approves any claim, any right for any incentive under the policy or recommends acceptance of the claim, the unit shall not be deemed to have satisfied the conditions of the policy.
- (k) No claim can be made for any incentive under the policy without the eligibility certificate issued under the policy by the concerned implementing agency and the unit will have to comply with the actual conditions of the eligibility certificate to the satisfaction of the competent authority.
- (l) The decisions of the implementing agency shall be final and binding subject to such directions as may be issued by the Government from time to time in this regard.
- (m) A unit after obtaining the eligibility certificate shall be eligible to apply for all kinds of concessions, incentives, subsidies, reimbursements under this policy.

5. Provisional Eligibility Certificate (PEC)

- (a) Provisional eligibility Certificate is such a certificate which has been issued by the Competent Authority in this regard before undertaking commercial production/service operation for establishment of new unit or expansion of existing unit, exemption/concession of land rates from SIIDCUL and to claim reimbursement of stamp duty chargeable in respect of land leased or purchased.
- (b) To obtain provisional eligibility certificate under Mega Industrial and Investment Policy-2021, the concerned unit can apply online on the prescribed format with requisite records and certificates to the nodal agency after getting in-principle approval for establishment of new project/expansion of existing project under Single Window System.
- (c) After the online submission of the application form for provisional eligibility certificate, three copies of the printed / paper copy of the application form along with the requisite records will be submitted to the competent authority of the concerned nodal agency within 15 days.

(d) The nodal agency or its authorized representative will initially check the application form that the application form has been filled properly and whether the relevant records etc. have been attached with the application or not and the same shall be entered in the register maintained for this purpose. The Nodal Agency will forward the application form to SIIDCUL for scrutiny by the Scrutiny Committee expeditiously. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

(e) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for being placed before the State Level Committee.

(f) The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee. After approval of the application for eligibility certificate from the State Level Committee, the authorized officer of the nodal agency will issue the provisional eligibility certificate in the prescribed format within a week.

(g) After obtaining the provisional eligibility certificate, a unit under the policy will be eligible to apply for concession/rebate in land price and reimbursement of stamp duty charges from SIIDCUL.

(h) For establishment of new unit or expansion of existing unit, acknowledgment of IEM Part-A can be obtained from Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India and Department of Industry Promotion and Internal Trade (Secretariat of Industrial Assistance), Government of India or In-principle approval from competent authority under Single Window System.

6. **Eligible / Non-eligible items of civil works and plant & machinery**

a. **Eligible Civil Works:** The following civil works directly connected with manufacturing process/providing services shall be considered eligible for consideration as eligible civil works:-

- (i) Factory shed/building with utility areas directly involved in manufacturing and necessary ancillary processes i.e. Plant Stores, Quality Control, Power Room, Maintenance Workshop (actual or rates approved by Public Works Department, whichever is lower).
- (ii) Required residential facilities as per the effective SIDA standard as applicable.
- (iii) Construction of raw material and finished product warehouse in the factory premises (Actual or effective rates notified by Public Works Department, whichever is lower).
- (iv) Necessary civil construction works like machines, equipment (actual or effective rates of PWD schedule, whichever is less)
- (v) Engineer certificate will be submitted in the prescribed format

(vii) The actual cost of civil works shall be submitted in the prescribed format.

b. **Non-eligible civil works:** The following civil works directly connected with manufacturing process/providing services shall be considered as ineligible for consideration as Non-eligible civil works (list is not exhaustive).

- (i) Boundary Wall & Gate.
- (ii) Approach Road / Internal Road
- (iii) Office Building / Space utilized for office.
- (iv) Raw material / finished product godown situated at a different location other than factory premises.
- (v) Any residential building or rest house / guest house
- (vi) Cafeteria
- (vii) Labour rest room and quarters for workers.
- (viii) Security / Guard room or enclosures.
- (ix) Construction bridge load.
- (x) Consultancy fee, taxes etc.

c. **Eligible Plant & Machinery:**

- (i) Original price of machinery / equipment directly connected to manufacturing process
- (ii) Accessories like tools, jigs, dies, moulds directly connected to manufacturing process
- (iii) Motors connected with Plant & Machinery
- (iv) Machinery/equipment installation, erection and commissioning.
- (v) Transportation charges, Transit Insurance, VAT / CST, Excise Duty, Entry Tax etc. paid (in case of indigenous machinery / equipment).
- (vi) Import duty, shipping charges, CVD, container handling charges, customs clearance charges, VAT / CST, transportation charges from port, entry tax etc. paid (in the case of imported machinery / equipment)
- (vii) Quality Control (R&D), Pollution Control and Fire Fighting Equipment.
- (viii) Electrical installations including internal electrification. Panel Board, dedicated transformer, gas producer plant, power generating set etc.
- (ix) Payment against all the above items must be made by A/c payee cheque/ Demand Draft / NEFT / RTGS which should be reflected in the Bank Statement to be submitted with the application for Eligibility Certificate

(x) Elevation and installation related charges paid on actual basis in the manufacturing sector

(xi) Chartered Accountant Certificate (CA Certificate) shall be submitted in the prescribed format.

d. Non-Eligible Plant & Machinery:

(i) Plant & Machinery not directly related to manufacturing process

(ii) Fuel, Consumables, Spares and Stores.

(iii) Computers and Office Furniture.

(iv) Vehicles

(v) Second hand / Old Machinery

(vi) Closed circuit CCV Camera and Security System related equipment.

(vii) Stationery items.

7. Others

- (a) **Scheduling of Capital Investment:** In case of any variation arising in the determination of capital investment, the State Level Committee/Approving Authority shall examine and decide the same
- (b) In case of existing unit under expansion, eligibility certificate will be submitted along with the application format, duly certified by the Chartered Engineer/Chartered Accountant for the assessment of plant & machinery/equipment and building and the certificate of capital investment. The capital investment of the unit for the extended purpose shall be calculated on the basis of capital investment made after expansion till the date of commercial production of the proposed product/operation of the service rendered
- (c) New units availing benefits/concessions/incentives under the policy and existing units undertaking expansion shall be eligible to apply for the concessions/financial incentives provided in the policy after six months of commencement of commercial production/operation of the service
- (d) The last date for investment in civil construction as well as plant and machinery shall be from the date of receipt of in-principle approval under single window arrangement to the date of commencement of commercial production/service operation as recorded in Udyam Registration/IEM-Part-B.
- (d) The disbursing agency shall ensure that funds are released against incentives, concessions, benefits, reimbursements by the State Level Committee subject to availability and allocation of funds sanctioned by the Government.

- (f) State Level Committee on the basis of the recommendation of the Scrutiny Committee on its claim/revised claim of an application or to approve on certain other valid grounds or to reject it or an application/claims may be kept pending for the purpose of non-availability of sufficient funds for the purpose as it deems fit.
- (g) If it is confirmed that an industrial unit has fraudulently attempted to obtain the financial incentives provided for in this policy by giving false information or if the unit ceases production within 5 years of commercial production/service operation, then After giving that unit an opportunity of being heard, such unit may be asked to return the grant or the financial assistance provided. This grant/reimbursement assistance will be released through digital payment and SIIDCUL can take an affidavit in this regard from the beneficiary industrial units. A contract will also be executed between the industrial unit and the disbursing agency SIIDCUL before distribution to the beneficiary unit fulfilling all the requirements of the scheme
- (h) The concerned authority may ask the unit to refund the amount availed of the benefits within a period of 30 days If the unit fails to do so, the authority may take legal action in a court of competent law for recovery of the amount along with interest thereon and such penal action as permissible under the law.
- (i) If any unit fails to undertake commercial production within a period of three years from the date of allotment of land or Proviso, eligibility certificate or issue of eligibility certificate, whichever is earlier, the benefits given under the policy can be withdrawn. From the date of commencement of commercial production, if any unit closes after three consecutive years of production, then the amount of grant/subsidy so approved by the concerned committee will be released to the concerned unit through their bank or financial institutions.
- (j) All eligible units shall submit an undertaking as per the prescribed format giving details that the information furnished along with the application form is correct.

8. Right to Modify /Amend etc.

- (a) The State Government shall have the right at any time to extend, modify or repeal any part of the Guidelines in the public interest
- (b) The State Government may, in appropriate cases, after careful consideration of profit and loss, make concessions in respect of the application or non-applicability of any particular provision of this policy
- (c) The State Government may, after careful consideration of appropriate matters, modify any incentive/benefit under the policy or extend any condition or impose additional conditions, if it so desires.

9. Miscellaneous (a) If any clarification is required regarding the implementation of these guidelines, the Department of Industrial Development, Government of Uttarakhand will be authorized to issue necessary clarifications in this regard.

(b) If there is any ambiguity in any matter, Industrial Development Department, Government of Uttarakhand will have the jurisdiction to interpret any of the provisions correctly.

10. Rectification of Mistake With a view to rectifying any error noticed on the records in the composition of the amount of grant under the policy. The Competent Authority may, by its order, distribute the grant to such unit and recover the excess payment, if any, at the rate of 12 percent per annum. No such order shall be issued for the benefits given under this scheme after a period of one year from the end of the financial year where the benefits have been fully availed.

11. Appeal (a) The State Level Committee shall have the power to hear and dispose of any appeal against the orders of the Competent Authority of the concerned Department/Implementing Agency/Disbursing Agency.

(b) An appeal can be made to the State Government against any order/decision of the State Level Committee.

(c) Application for appeal may be made within a period of 30 days from the date of communication of the decision.

12. Authority to issue Clarification / Modification / Refinement (a) The Uttarakhand government will have the right to amend/modify/clarify the policy as and when it is necessary in the public interest. However, as and when necessary, keeping in view the convenience in implementation of the draft policy attached to this policy, can be modified, changed, expanded or repealed by the Department of Industrial Development.

(b) If there is any ambiguity in any matter, Industrial Development Department, Government of Uttarakhand will have the jurisdiction to interpret any of the provisions correctly.

(c) The State Government may, in appropriate cases, after careful consideration of profit and loss, make concessions in respect of the application or non-applicability of any particular provision of this policy.

(d) Department of Industrial Development, Government of Uttarakhand shall have the authority to issue necessary clarification in case any clarification is sought regarding implementation of these guidelines / rules.

(e) Department of Industrial Development shall have the right to correctly interpret any provision of these guidelines in case of any ambiguity.

Chapter-Two

Benefits/Concessions/Incentives to Eligible Units

13. Allotment of land through SIIDCUL

- a. The allotment of land to the willing applicants under these provisions will be done by SIIDCUL under single window system as per the guidelines as decided from time to time and effective rates of SIIDCUL.
- b. Based on the provisional eligibility certificate issued by the Competent Authority under this policy in allotment of land, a special discount/concession of 15 percent for large projects, 25 percent for mega projects and 30 percent for ultra mega & super ultra mega projects will be given at the effective rates of SIIDCUL.
- c. Under this policy, 20% of the value of land allotted by SIDCUL (after rebate) will be paid at the time of allotment of land and balance amount will be payable in equal installments of 5 years along with fixed interest.

14. Incentives and other concessions under the policy for eligible Large/Mega/Ultra Mega/Super Ultra Mega Projects

- i. Reimbursement of Seven percent interest assistance will be provided to eligible units on term loans for the next five years from the date of commencement of commercial production, with a maximum annual limit of Rs 25 lakh, Rs 35 Lakhs, Rupees 50 Lakhs and Rupees 75 Lakhs for Large, Mega, Ultra Mega And Super Ultra Mega projects respectively .
- ii. The maximum limit and quantum of reimbursement of net SGST payable after adjustment of Input Tax Credit (ITC) on B2C sale of finished goods shall be as under:-
 - (a) 30% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for Large Projects, sold to customers (B to C) within the state.
 - (b) 50% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for Mega Projects / Ultra Mega Projects / Super Ultra Mega Projects, sold to customers (B to C) within the state.

Explanation:

- (i) Whatever tax liability is created under the Goods and Services Tax Act, the entire amount related to it will be deposited in the treasury and no part will be kept with itself. Reimbursement of part of such SGST tax paid under Goods and Services Tax (GST) paid to the entity in accordance with the provisions of this scheme in view of the total tax liability after adjustment of ITC as per the return filed and which is related to the sale directly to the customer (B2C) within the state.
- (ii) The benefit of SGST reimbursement assistance will be admissible to manufacturing industries only.

iii. Reimbursement assistance will be admissible to the eligible enterprises at the rate of Rs.1.00 per unit in the electricity bill payable for the next 5 years from the date of commencement of production. The maximum annual limit of electricity reimbursement assistance will be Rs 50 lakh per annum for large projects, Rs 75 lakh per year for mega projects, Rs 1 crore per year for ultra mega projects and Rs 1.50 crore per year for super ultra mega projects.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance payable in electricity bill to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals etc. included in the eligible service activities identified under the policy will not be admissible.

iv. The eligible enterprises will be reimbursed 100% of the electric duty due/paid on the electricity bill consumed in the production work for the next 5 years from the date of commencement of production to the eligible enterprises.

Explanation: The benefit of reimbursement assistance will not be admissible on electric duty paid to hotels, resorts, ropeways, motels, hospitals, etc. included in the eligible service activities identified under the policy.

v. Reimbursement assistance of 50 percent will be given on the stamp duty charges payable in the execution of land purchase deed and lease deed

vi. Reimbursement of registration fee payable / paid for execution of Land purchase / lease deed @ of Rs. 999 per Rs 1000 shall be given.

vii. Capital subsidy up to 30%, subject to a maximum of Rs. 50 lakh, will be payable on the establishment of an ETP plant.

viii. **Payroll Assistance to encourage massive employment generation:** There shall be a minimum specified limit of regular employment of 50 people for large projects, 100 for mega projects, 200 for ultra mega projects and 400 for super ultra mega projects for allowing payroll assistance. Enterprises where regular employees are employed in excess of the specified limit, shall be given pay-roll assistance as gratuity at the rate of Rs.500/- per employee per month for the next 5 years on the employees employed in addition to the specified limit. For women employees, this rate shall be Rs 700/- per employee per month

Chapter-Three

Provisions, Procedures and Disbursement of Benefits

15. Reimbursement of Interest Subsidy:

(a) Provision for reimbursement of interest assistance.

(i) Units receiving any similar benefits or incentives or subsidies under any other scheme/benefits of the Central Government or State Government shall not be eligible to receive benefits under this scheme.

(ii) Reimbursement of Interest Subsidy will be admissible on term loans taken from nationalized banks / scheduled commercial banks and other financial institutions recognized by the Reserve Bank of India for financing. Any term loan taken before the commencement of the policy, the first instalment of which has been disbursed before the commencement of this policy, the benefit of reimbursement of interest subsidy will not be admissible.

(iii) Reimbursement of Interest Subsidy will be admissible for a period of five years or till the period of repayment of loan, whichever is earlier. The period of reimbursement of interest subsidy will be taken into account from the date of disbursement of the first instalment to the permissible period.

(iv) Reimbursement of Interest Subsidy will be given to such units which have regularly paid instalment and interest to financial institutions/banks. If the unit is fail in this, the reimbursement of interest subsidy for the failure period will not be given and such failure period will be deducted from the period of five years as mentioned in above Sub Clause (i.i) of above

(b) Procedure for claiming Reimbursement of Interest Subsidy:

(i) The eligible units desirous of availing the reimbursement of interest subsidy under the policy will have to submit the claim of reimbursement of interest subsidy on the prescribed format on the www.investuttarakhand.com portal under single window system along with the requisite documents. Along with, the application for reimbursement of interest subsidy a certificate from the concerned bank/financial institution to the effect that the unit is repaying the principal and interest regularly, will have to be submitted. Banks will also mention in the certificate any failure to repay the principal interest. The first application for the claim of reimbursement of interest subsidy will be made within 45 days after the commencement of commercial production. Thereafter claims will be submitted on quarterly basis within 45 days after the end of the quarter.

(ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on the www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIDCOUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIDCOUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete incomplete applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

(iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State Empowered Committee.

(iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next

meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.

- (v) The State Empowered Committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State Empowered Committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for reimbursement of interest subsidy, it shall give such unit an opportunity of being heard and shall record the reasons for the refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement of Reimbursement of Interest Subsidy:

- (i) Reimbursement of Interest Subsidy will be disbursed only after the commencement of commercial production.
- (ii) The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency, on receipt of intimation from the Member Secretary, State Level Committee, shall pass an order for reimbursement of the approved claim amount subject to the availability of funds for the purpose and the approved amount will be transferred immediately to the concerned unit through Demand Draft Pay Order/Cheque/RTGS directly into the bank account.

16. Electricity Subsidy / Electricity Bill Subsidy

(a) Provision for Electricity Assistance:

- (i) Eligible units will be given this assistance for the next five years after the date of commencement of commercial production.
- (ii) Large, Mega, Ultra Mega And Super Ultra Mega Projects will be given reimbursement assistance at the rate of Rupee 1 per unit for the next five years after commencement of commercial production, on the basis of electricity consumed in the production work up to the maximum specified limit. The maximum annual limit of electricity reimbursement assistance will be Rs 50 lakh per annum for large projects, Rs 75 lakh per year for mega projects, Rs 1 crore per year for ultra mega projects and Rs 1.50 crore per year for super ultra mega projects.
- (iii) 100% reimbursement of electricity surcharge to eligible manufacturing units for the next five years after the date of commencement of commercial production.
- (iv) Reimbursement of one rupee per electricity surcharge paid and power unit consumed shall be applicable only on single connections given to units for industrial use for manufacturing/generation or for related purposes only.

(b) Procedure for claiming Electricity Assistance:

- (i) Eligible units will apply online on the prescribed format to the nodal agency for electricity reimbursement assistance and reimbursement of electricity surcharge. The eligible unit shall submit its first claim within 45 days after the commencement of commercial production. Thereafter on quarterly basis the claims will be submitted within 45 days after the end of the quarter.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investintarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall

initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SHDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing examining the applications received from the level of SHDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for Electricity Assistance/ Electricity Bill Subsidy, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and a concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Distribution of Electricity Assistance:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

17. Stamp Surcharge:

(a) Provision for exemption/reimbursement of stamp surcharge:

Eligible units will be reimbursed 50% of the payment of stamp surcharge on land purchase/execution of land lease.

(b) Procedure for Exemption of Stamp Surcharge:

- (i) The units eligible for expansion of the existing unit or for setting up a new unit under this policy shall submit the duly filled application form in the prescribed format to the Nodal Agency in the format "Application for Claim for Reimbursement of Stamp Surcharge". Within 45 days after the execution of the deed, the claim of reimbursement assistance will be submitted along with the provisional eligibility certificate and an affidavit will have to be attached in support of the facts mentioned in the application form.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled

and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for exemption/reimbursement of stamp surcharge, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for reimbursement of stamp surcharge paid:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

18. Reimbursement of Registration Fee:

(a) Provision for reimbursement of registration fee:

Under this policy, the eligible unit will be given a reimbursement assistance of Rs 999 on registration fee of Rs 1000 in respect of fee paid for registration of purchase deed/lease deed.

(b) Procedure for claiming reimbursement of registration fee:

- (i) Eligible unit desirous of availing reimbursement of registration fee paid, shall submit a duly completed application form "Application for reimbursement of registration Fee" in prescribed format along with details of registration fee paid along with proof of payment duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency within 45 days of registration of land purchase/lease deed.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter

the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing / examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / non-genuine applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub clause (i) the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State Level Committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.
- (v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.
- (vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for reimbursement of registration fee, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for the refusal in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/cheque RTGS to the concerned unit expeditiously.

19. Capital subsidy on ETP:

- (a) **Provision for subsidy for setting up of ETP plant:**
 - (i) Under the policy, eligible projects/units will be given capital subsidy assistance of 30 percent on the installation cost of the ETP plant, subject to a maximum of Rs 50 lakh.
 - (ii) A unit receiving similar subsidy under any other scheme/package of the Central/State Government shall not be eligible for capital subsidy under this policy.
 - (iii) Subsidy for setting up of ETP will be calculated on fixed capital investment directly linked to the establishment of ETP.
 - (iv) Eligible units can submit subsidy claim for installation of ETP after successful completion of ETP plant.

(b) Procedure for Submission of Gratuity Claim on Establishment of ETP:

- (i) Eligible unit desirous of availing subsidy on establishment of ETP, shall submit a duly completed application form "Application for claim of Subsidy for ETP" in prescribed format along with details of Bill vouchers along with proof of payment duly certified by Chartered Accountant and an affidavit in support of the facts of the application, to the Nodal Agency within 45 days of successful completion of ETP unit.

(ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SIIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing examining the applications received from the level of SIIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / ineligible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

(iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i), a maximum delay of 90 days in submission of the application from the prescribed date of application may be considered with the approval of the State empowered committee.

(iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State empowered committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.

(v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.

(vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for subsidies for setting up of ITP, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for refusal in writing. The decision of the committee will be communicated by the nodal agency or the state empowered committee to the unit and all concerned immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/cheque/RIGS to the concerned unit expeditiously.

20. Payroll Assistance to encourage massive employment generation:

(a) Provision for Payroll Assistance:

(i) There will be a minimum specified limit of regular employment of 50 people for large projects, 100 for mega projects, 200 for ultra mega projects and 400 for super ultra mega projects for allowing payroll assistance. Enterprises where regular employees are employed in excess of the specified limit, will be given payroll assistance as gratuity at the rate of Rs.500/- per employee per month for the next 5 years on the employees employed in addition to the specified limit. For women employees, this rate will be Rs. 700/- per employee per month.

(ii) Additional employee means the number of employees in excess of the specified number of employees employed.

(iii) Unit availing similar subsidy under any other scheme/package of Central/State Government will not be eligible for capital subsidy under this policy

(b) Procedure for Claiming Payroll Assistance:

(i) Eligible unit desirous of availing reimbursement of payroll assistance shall submit a duly completed application form "Application for claims of payroll assistance" in prescribed format along with details of facts/evidences and details certified by the Labor Department, to the Nodal Agency within 45 days of the employment of more than the specified number of employees.

(ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of on line submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative shall initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager SEDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing, examining the applications received from the level of SEDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete and illegible applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.

(iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in clause 6(b)(i) of Chapter II, the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.

(iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 10 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State empowered committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the Scrutiny Committee.

(v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the timelines immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.

(vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for payroll assistance, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record, writing the reasons for the denial. The decision of the committee will be communicated to the unit and a concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) Procedure for Disbursement:

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RGS to the concerned unit expeditiously.

21. Reimbursement of SGST:

(a) Provisions for SGST:

- (i) The industrial unit-project will get its enterprise registered under the Goods and Services Tax Act, 2017
- (ii) The maximum limit and quantum of reimbursement of net SGST payable after adjustment of Input Tax Credit (ITC) on B2C sale of self-made goods/items shall be as under -
 - (A) 30% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for large projects, sold to customers (B to C) within the state
 - (B) 30% of the total net SGST tax liability after adjustment of Input Tax Credit for the next 5 years from the date of production for Mega Projects / Ultra Mega Projects / Super Ultra Mega Projects, sold to customers (B to C) within the state.

Explanation:

- (i) Whatever tax liability is created under the Goods and Services Tax Act, the entire amount related to it will be deposited in the treasury and no part will be kept with itself. Reimbursement of part of such SGST tax paid under Goods and Services Tax (GST) paid to the entity in accordance with the provisions of this scheme in view of the total tax liability after adjustment of ITC as per the return filed and which is related to the sale directly to the customer (B2C) within the state.
- (ii) The benefit of SGST reimbursement assistance will be admissible to manufacturing industries only.

(b) Procedure for Reimbursement of SGST:

- (i) According to the provisions of the Goods and Services Tax Act, monthly / quarterly return will be filed by the eligible manufacturing units first and according to the return, whatever tax liability is created under the State Goods and Services Tax (SGST) Act, the entire amount will be deposited in the treasury and no part will be kept with itself. According to the return filed and considering the total tax liability after adjustment of ITC, the unit will be reimbursed the part of such SGST paid under the State Goods and Services Tax (SGST) paid in accordance with the provisions of these guidelines. Which is related to the sale directly to the customer (B to C) within the state.
- (ii) The application form will be submitted to the concerned nodal officer in the prescribed format on www.investuttarakhand.com portal. In case of online submission, three sets of print of the application form along with all the attached documents will also be submitted to the nodal agency after due signature. The nodal agency or its authorized representative will initially check the application form whether the application form has been properly filled and whether the relevant records etc. have been attached with the application and shall enter the same in the register maintained for the purpose. Thereafter, the application form will be forwarded to the General Manager, SJIDCUL to be presented before the Scrutiny Committee at the earliest. After scrutinizing examining the applications received from the level of SJIDCUL, they will be presented for the scrutiny of the Scrutiny Committee. Incomplete / incomplete applications will be returned to the concerned unit along with the reasons.
- (iii) Where the application is submitted after the time period as provided above in sub-clause (i) the maximum delay of 90 days in the submission of the application from the prescribed date of application may be allowed on the approval of the State empowered committee.
- (iv) The Scrutiny Committee will examine the application and return it to the Nodal Agency with its recommendation within 30 days for placing it before the State Level Committee. The Nodal Agency will place the application before the State empowered committee in the next meeting in the order of receipt of the application along with the recommendation of the

Scrutiny Committee.

(v) The State empowered committee will take a decision after considering the applications recommended by the Scrutiny Committee. Information about the decision taken by the State empowered committee by the nodal agency, which will contain the details of the date of the meeting, the sanctioned amount, the minutes. Immediately after the decision taken in the meeting, which shall not exceed seven days from the date of the meeting, shall be forwarded to all the parties concerned and to the disbursing agency.

(vi) Where the State Level Committee is of the opinion that the unit is not eligible for SGST reimbursement assistance, it shall provide such unit an opportunity of being heard and record the reasons for denial in writing. The decision of the committee will be communicated to the unit and all concerned by the nodal agency of the state empowered committee immediately after but within a maximum of seven days from the date of the decision taken by the state level committee meeting.

(c) **Procedure for Disbursement:**

The designated disbursing agency or any officer authorized by the disbursing agency shall, on receipt of intimation from the nodal agency, pass an order for reimbursement of the approved claim amount, subject to availability of funds for the purpose and will transfer it directly to the bank account through Demand Draft/Pay Order/Cheque/RTGS to the concerned unit expeditiously.

Chapter-Four

Application Form, Format, Appendix and Enclosure for applying for various Incentives/Benefits/Concessions

The application forms, formats, appendices and attachments for various incentives/benefits/concessions etc. under the policy are as follows. These may be modified or modified by the implementing agency, nodal agency or disbursing agency in such new formats and structures as may be required from time to time:

S.No.	Description	Form Details
1.	Scrutiny Committee	Appendix 1
2.	Application for eligibility certificate (new unit)	EC-1
3.	Application for Certificate of Eligibility (Existing Unit)	EC-1 A
4.	Format of Certificate of Eligibility	EC-2
5.	Application for provisional eligibility certificate	PEC-1
6.	Format of Provisional Eligibility Certificate	PEC-2
7.	Application for Claim of Interest Subsidy	Claim (INT)
8.	Application for Claim of Reimbursement of SGST	Claim (claim)
9.	Application for claim of subsidy-electricity assistance in electricity bill	Claim (PBR)
10.	Application for claim of reimbursement of stamp surcharge	Claim (STD)
11.	Application for claim of reimbursement of registration fee	Claim (RGF)
12.	Application for claiming subsidy of ETP	Claim (ETP)
13.	Application for claim of payroll assistance	Claim (PRA)
14.	Format of Engineer Certificates (for all new units)	Engineer (New Unit)
15.	Format of Engineer Certificates (For Existing Units)	Engineer (Existing Unit)
16.	Statement of Actual Cost of Civil Work	-
17.	Details of investment on plant & equipment and other property	-
18.	Format of Chartered Accountant Certificate (New Entity)	CA-1
19.	Format of Chartered Accountant Certificate (Existing Entity)	CA-2
20.	Form of affidavit	affidavit
21.	Form of undertaking	Enterprise

Appendix A
Scrutiny Committee

-- S.No.	Members of Committee	Designation
1.	Principal Secretary / Secretary (Industries), Govt. of Uttarakhand,	Chairman
2.	Director General and Commissioner Industries, Uttarakhand or their representatives who are of the level of Director Industries.	Member
3.	Managing Director, SIIDCUL	Member
4.	Additional Secretary, Finance, Government of Uttarakhand.	Member
5.	Director, Finance / Finance Controller, SIIDCUL	Member
6.	General Manager, SIIDCUL	Member Secretary

By Order,

DR. PANKAJ KUMAR PANDEY,
 Secretary



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुक्मी, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ₹0 (माघ 29, 1944 शक सम्वत)

भाग 1—क

नियम, कार्य-विधियां, आङ्गाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि यिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल भूमोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 21/XIV-a/59/Admin.A/2012--Ms. Payal Singh Civil Judge (Sr. Div.), Kashipur District Jdham Singh Nagar is hereby sanctioned child care leave for 18 days w.e.f. 06.12.2022 to 23.12.2022.

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 22/XIV-a-15/Admin.A/2009--Shri Bhavdeep Ravtey Civil Judge (Sr. Div.), Rishikesh District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 18 days w.e.f. 05.12.2022 to 22.12.2022.

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 23/XIV-14/Admin.A/2008 -Shri Dharmendra Singh Adhikar 5th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 29 days w.e.f. 07.11.2022 to 05.12.2022

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 24/XIV-35/Admin A/2008--Shr. Ramesh Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 12.12.2022 to 24.12.2022, with permission to prefix 10.12.2022 & 11.12.2022 as second Saturday & Sunday holiday and suffix 25.12.2022 to 31.12.2022 as Christmas holidays & 01.01.2023 as New Year holiday respectively.

NOTIFICATION

January 18, 2023

No. 25/XIV-a-40/Admin.A/2020--Ms. Pratiksha Kesarwan, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.) Roorkee, Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 29 days w.e.f. 19.11.2022 to 17.12.2022, with permission to suffix 18.12.2022 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्डकार्यालय आदेश

31 दिसम्बर, 2022 ई०

पत्रांक 1264 / सू.एवंलौ.स.यि.(पशा.)—31/2011—सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री पान सिंह विष्ट को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वैकासन मैट्रिक्स में लेवल-10 वेतनमान ₹ 56100—177500 के एवं पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2 श्री पान सिंह विष्ट की पदोन्नति श्री गोपाल सिंह राणा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाले एक परिणामी रिकित के ग्राहीन दिनांक 01 जनवरी, 2023 अधधा चसके उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3 उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ल्योन्स कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री पान सिंह विष्ट को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रत्यावर्त्तित कर दिया जायेगा।

कार्यालय आदेश

31 दिसम्बर, 2022 ई०

पत्रांक 1265/सू.एवंलो संवि (प्रशा.) 34/2007 सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 वेतनमान रु० 47600-151100 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करवे हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है ।—

1. श्री हरेन्द्र सिंह

2. श्री मुकेश कुमार

2. उपरोक्त क्रमांक-1 पर अकित कार्मिक श्री हरेन्द्र सिंह की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी तथा क्रमांक-2 पद अकित कार्मिक श्री मुकेश कुमार की पदोन्नति श्री पान सिंह विष्ट वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदोन्नति पद (भुल्य प्रशासनिक अधिकारी) पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त रिक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिये आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को प्रधान सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

बंशीधर तिवारी,
प्रधानिदेशक।

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि०, नैनीताल

कार्यभार प्रमाणक

01 जनवरी, 2023 ई०

संख्या कैम्प/2-प्रभाण्डित किया जाता है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुग्राम-1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश File No PVD 1-JAS.JAG.1/2022 XXX-1 (Computer No. 44239) 1/85119/2022 देहरादून, दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के अनुपालन में कमिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान रु० 15,600-38,100 + ग्रैंड पे रु० 7800/- (पे मैट्रिक्स लेवल 12) के पद का कार्यभार अधोहस्ताक्षरी द्वारा आज दिनांक 01 जनवरी, 2023 के पूर्वाहन में ग्रहण किया गया।

अवमोचक अधिकारी,
विनीत तोमर।

कार्यालय—अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यभार प्रमाण पत्र

06 जनवरी, 2023 ई०

पत्रांक वाकअधित्र०/अधिष्ठान/व्य०प०/७६(५)/०५(१०)/२०२३—प्रसारित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग ८ द्वारा निर्गत अधिसूचना सं० ८६१५२/२०२२/०७(१००)/XXVII(८)/२००८, दिनांक २८-१२-२०२२ के क्रम में भाननीय उत्तराखण्ड राज्य न्यायालय, गैनीताल की अधिसूचना संख्या ०./UHC/Admin/LA/2023 दिनांक ०२-१-२०२३ के अनुक्रम में 'अध्यक्ष, वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून' के पद का कार्यभार का आज दिनांक ०६-१-२०२३ की पूर्वाह्न में निम्नप्रकार हस्तान्तरित किया गया।

अवमुक्त अधिकारी,

अवमोचक अधिकारी,

सी०पी० विजलदान,
ए०ज०००८०

मलिक मजहर सुलतान,
ए०ज०००८०
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुद्रकी, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ई0 (नाघ 28, 1944 शक सम्वत)

भाग ३

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोस-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एसिया, दाउन एसिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निवेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं०) हरिद्वार

सूचना

०८ फरवरी, 2023 ई०

पत्रांक १८९०/प०च०/२०२३-राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-१३१७/राजनि०आ०/०२/४०७६/२०२३ दिनांक ०८ फरवरी, २०२३ के द्वारा जनपद हरिद्वार की सभरत ग्राम पंचायतों में उप प्रधान ग्राम पंचायत के नियोगन निम्न प्रकार समय सारणी के अनुसार कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं -

समय सारणी

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन चिन्ह आवृत्ति करने का दिनांक व समय	भत्तदाता का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
१	२	३	४	५	६
१८.०२.२०२३ (पूर्वाह्न १०.०० बजे से पूर्वाह्न ११.०० बजे तक)	१८.०२.२०२३ (पूर्वाह्न ११.०० बजे से मध्याह्न १२.०० बजे तक)	१८.०२.२०२३ (मध्याह्न १२.०० बजे से अपराह्न १२.३० बजे तक)	१८.०२.२०२३ (अपराह्न १२.३० बजे से अपराह्न ०१.३० बजे तक)	१८.०२.२०२३ (अपराह्न ०१.३० बजे से अपराह्न ०३.३० बजे तक)	१८.०२.२०२३ (अपराह्न ०४.०० बजे से कार्य की समाप्ति तक)

ઉપ પ્રધાન કે નિર્વાચન-2023 હેતુ ગ્રામ પંચાયતો કા વિવરણ-

કોડ્યો	વિકાસ ખણ્ડ કા નામ	ગ્રામ પંચાયતો કી સંખ્યા	ગ્રામ પંચાયતો મેં ઉપ પ્રધાનો કી સંખ્યા
1	2	3	4
1	બહાદરાબાદ	80	80
2	ભગવાનપુર	54	54
3	સાલુકો	46	45
4	નરસન	63	63
5	લંકસર	51	51
6	ખાનપુર	25	25
	યોગ-	318	318

રાજ્ય નિર્વાચન આયોગ કી ઉકૂલ અધિસૂચના કે કમ મેં ઉઠ્પ્રો પંચાયતીરાજ (સરસ્યો, પ્રધાનો ઔર ઉપ પ્રધાનો કા નિર્વાચન) નિયમાબલી, 1984 (ઉત્તરાખંડ મેં યથાપ્રવૃત્ત) કે નિયમ-117 (1) મેં પ્રદત્ત શક્તિયો કા પ્રયોગ કરતે હુયે હોય મેં, વિનય શાંકર પાણ્ડેય, જિલ્લા માર્જિસ્ટ્રેટ/જિલ્લા નિર્વાચન અધિકારી (પો) હરિદ્વાર, ઉકૂલ સમય સારણી કે અનુસાર જિલ્લા હરિદ્વાર કી સમરલ ગ્રામ પંચાયતો મેં ઉપ પ્રધાન ગ્રામ પંચાયત કે નિર્વાચન સમ્પન્ન કરાયે જાને કે લિએ દિનાંક 18.02.2023 કો જિલ્લે કી સમસ્ત ગ્રામ પંચાયતો કી બૈઠક ગ્રામ પંચાયત મુખ્યાલય પર આનુભૂતિક કરતા હોય યાં બૈઠક ગ્રામ પંચાયત મુખ્યાલય કે પંચાયત ભવન, ગ્રાધમિક વિદ્યાલય અધ્યાત્મ કિસી સાર્વજનિક સ્થાન પર આયોજિત કી જાયેગી, ઉપ પ્રધાન કે નિર્વાચન કે લિયે આવશ્યક પરિવર્તનો કે સાથ વહી પ્રક્રિયા અપનાઈ જાયેગી, જો ગ્રામ પંચાયત મેં પ્રધાન પદ કે નિર્વાચન કે લિયે લાગુ હૈ, ઉપ પ્રધાન પદ હેતુ નામ નિર્દેશન પત્ર પ્રસ્તુત કરને ઉનકી જાત્ર નામ વાપસી નિર્વાચન ચિન્હ આવટન, મનુદાન તથા સત્તગણના કા કાર્ય એવ પરિણામ કી ઘોષણા સમ્વનિધિત ગ્રામ પંચાયત મુખ્યાલય પર કરાયી જાયેગી

નામ નિર્દેશન પત્રો કી બિકી ક્ષેત્ર પંચાયત મુખ્યાલય પર દિનાંક 10 ફરવરી 2023 સે 16 ફરવરી 2023 તક (અવકાશ દિવસ કો છોઝકર) પૂર્વાન્હ 10:00 બજે સે અપરાન્હ 05:00 બજે તક તથા દિનાંક 10 ફરવરી 2023 કો 08: બજે સે 09:30 બજે તક સમ્વનિધિત ગ્રામ પંચાયત મેં નિર્વિષ્ટ સ્થાન પર કી જાયેગી નામ નિર્દેશન પત્રો કી બિકી કી સૂચના કા વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર કિયા જાયેગા

વિનય શાંકર પાણ્ડેય,
જિલ્લા માર્જિસ્ટ્રેટ/
જિલ્લા નિર્વાચન અધિકારી (પો)
હરિદ્વાર।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुडकी, शनिवार, दिनांक 18 फरवरी, 2023 ई० (माघ 29, 1944 शक सम्वत)

भाग ४
सूचना। इस अध्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने अपना नाम शादी के उपरान्त निर्मला से बदलकर निर्मला रावत कर लिया है भविष्य में गुज़े निर्मला रावत पत्नी श्री यजुवेन्द्र कुमार रावत के नाम से जाना पड़वाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ भेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

निर्मला रावत पत्नी श्री यजुवेन्द्र कुमार रावत
निवासी 17-A, भद्राकिनी कॉलोनी एस बी आई.
बैंक के पास मोहनपुरा नौहम्मदपुर, रुडकी
जिला हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-रुद्रप्रयाग

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली

उपविधि 2018

०६ दिसम्बर, २०१८ ई०

पत्रांक ४१३/न०प०तिः०(उप०गज०न००) / २०१८-२०१८-

१. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

क- यह उपविधि नगर पंचायत तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) 'विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि 2018' कहलायेगी।
ख- यह उपविधि नगर पंचायत तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) की सीमा में पृष्ठत होगी।
ग- यह उपविधि नगर पंचायत तिलवाडाहारा प्रख्यापित अधवा शासकीय गजट में प्रकाशन की रिक्षि से प्रकृत होगी।

२. परिसाधारे-

किसी विवर या प्रसार से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडासे हैं।
- (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत तिलवाडाकी सीमाओं से है।
- (ग) "अधिकारी सीमा" का तात्पर्य अधिकारी अधिक री नगर पंचायत तिलवाडासे है।
- (घ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य कानून पश्यायत तिलवाडाके अध्यक्ष/प्रश्न सक रहे हैं।
- (ङ) होटे का तात्पर्य नगर पंचायत तिलवाडाके निवायित अध्यक्ष/सदस्यों अध्यया प्रशासक रहे हैं।
- (च) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम-१९१६ (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)

संहोषन एवं उपायन आंश-२००२ से है।

(ज) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगर पंचायत तिलवाडाकी सीमान्तर प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पर होटिंग रेनर पोर्टर एवं अन्य भ्रमार शामिल हो है।

३. विज्ञापन पट्टा (होटिंग/यूनिपोल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानांतर लगाये जायेंगे। छोटे यूनिपोल येहि सर्फेस से २५ मीटर की दूरी पर ५ × ३ फिट एवं सड़क से ८ फुट ऊंचाई पर होंगे। मुख्य साधारण राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनिपोल के बीच कम से कम ३० फिट की दूरी होगी।

४. होटिंग/यूनिपोल सड़क से भगानानार लगाये जायेंगे जिससे यातायात सुगमता से संवालित हो सके एवं होटिंग के यूनिपोल/होटिंग सड़क से भगानानार लगाये जायेंगे जिससे अधिक आदि आदि गैंग गैंग गैंग का २५ कार्य सड़क दुर्घटना को न होने देने के उद्देश्य से जहां अवश्यकता होगी वहां रो इन यूनिपोल/होटिंग का २५ डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ते पर सड़क के समानांतर लगे के गिरदशा दिये जा सकते हैं।

**५. होटिंग/यूनिपोल का अधिकालम साईज २० × १० फिट होगा।
६. होटिंग/यूनिपोल सड़क की पेटिंग सर्फेस से न्यूनतम २५ मीटर दूरी पर लगाये जायें।
७. होटिंग/यूनिपोल की संरक्षण सजूत व फेम के आकार की हो ती धार्हिये जिससे आधी आदि गैंग गैंग गैंग का २५ संरक्षण सड़क दुर्घटना को न होने देने के उद्देश्य से जहां अवश्यकता होगी वहां रो इन यूनिपोल/होटिंग का २५ डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ते पर सड़क के समानांतर लगे के गिरदशा दिये जा सकते हैं।
८. शीराहा घोड़ों पर २५-२५ मीटर दूरी तक होटिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।
९. प्रान्तीक होटिंग की सम्बन्ध में सड़कवर एक धूनीक कोड नावर तथ किया जायेगा जिसके विवरण में उस होटिंग का आकार प्रकार होटिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान शीर्कृति तिथि रसीद नम्बर व उस होटिंग का सड़क से एंगल भी दर्जित किया जायेगा।**

१०. नगर पंचायत सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सि यौं द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से सूर्य नगर पंचायत कायोलेय गैंग पसीकरण कराया जायेगा इस प्रकार केंजल पजीकृत एजेन्सियों जो ही विज्ञापन। पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पलीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में १ अप्रैल से ३१ मार्च तक किया जायेगा।

११. नगर पंचायत तिलवाडामें विज्ञापन एजेन्सियों को पजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पजीकरण राशि १०,००,०००.०० (दस हजार एवं पश्यायत कोष में जम करायी होगी तत्पश्यायत पजीकृत एजेन्सी आले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु ५,०००/- (पाँच हजार) की धनराशि नवोनीकरण के सम में नगर पंचायत कोष में जमा करायेगा।

१२. नगर पंचायत सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों/फोल व्योरक का न्यूनतम शुल्क प्रति वर्ग फिर की दर से अ.प्रै., विज्ञापन जायेगा। शुल्क निम्नानुसार होगा। प्रत्येक वर्ग के पश्यायत शुल्क गैंग १० प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी भवन विज्ञापन शुल्क को न्यूनतम राशि होटिंग की सापेजानेक नील मी करायी जायेगी।

अनुसूची

क्र० सं०	विवरण	दर (रुपौ रूपौ)	यूनिट
१	मुख्य गांग (एन०एच०/प्रासीय मार्गों) के किनारे स्थित विज्ञापन/होड़िग्स (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हों)	130.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
२	नगर पंचायत के मुख्य मार्ग एवं आनंदिक मौहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगाने वाले विज्ञापन होड़िग्स आदि	70.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
३	इंडीकेटर गोर्ड (आई०एच०पी०) (३×२ फिट) बोल क्योवर २ (३×२ फिट)	800.00	प्रति पोल/प्रतिलंब प्रति पोल/प्रतिलंब
४	दुकानों/भवनों पर लगे रोलस्ट्राइन बोर्ड	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
५	दुकानों/भवनों पर लगे साइन बोर्ड	60.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
६	फ्लाईओवर कॉलम (१०×२० फिट)	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
७	पुल/पुल के कॉलम पर (१०×२० फिट)	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
८	प्रोटेक्शन लॉम/नाला क्लॅपर्ट (८×१५ फिट)	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
९	गिजी बस/पर्सिक बस एडवरटाईजिंग ४×१५ फिट (दोनों साइड) दो लाइन ३×३ फिट	40.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१०	डिलवरी वाहन/सर्विस वाहन/ट्रैक्टरी	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
११	डिग्रेटेशन वाहन	400.00	प्रतिदिन
१२	ट्रिले, ऐप ८०×२० फिट	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१३	पार्किंग दो डिस्ट्रॉले बोर्ड) ३×५ फिट	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१४	ट्री-गाड़ १५×१५ फिट	60.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१५	ट्रॉफिक बैशीकाटिंग	400.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१६	ट्रॉफिक पास्ट के ऊपर किसीसक २×३ फीट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१७	सार्वजनिक शौचालय दो साइड वाल ८×१० फिट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१८	रोड डियाइडर पर यूनिपोल गैन्ट्री ४०×४ फिट	200.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
१९	लाउडरपीकर द्वारा प्रचार अमेरिका द्वारा के लिए	100.00	प्रतिदिन
		50.00	प्रति दिन
२०	इंवेंट एण्ड एक्जीविशन/पेटो एक दिन का अतिरिक्त ड्रिंग के लिए	8,000.00/800.0	प्रतिदिन
२१	स्थानीय कॉबल्स नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क	80,000.00	वर्गफिट
२२	बस शल्टर २६×५ फिट	80.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
२३	बिजली/टेलीफोन के खालों पर ३×२ फिट	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिलंब
२४	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	150.00	प्रति बैलून अलेक्ट्र

प्रतिबन्ध यह है कि मेला के दिन अध्या फैला है लगाने वाले विज्ञापन का शुल्क प्रतिदिन ती दर से दुगुगा हिंग जायेगा।

3. નિમનલિખિત ક્ષેત્રોની કો વિજ્ઞાપન કી દૃષ્ટિ સે વિજ્ઞાપન પટ્ટ પ્રતિબન્ધિત રહેગા-

- 1-નદી કે કિનારે સ્થિત સમાવેશિત નિય જાને વાલે ગ્લોસાઈન/સાઈન બોર્ડ જો દુકાનો કે નામ કે સાથ યા સ્વાચ્છ રૂપ સે કિસી વસ્તુ કે વિષય, ગુણ આદે કે બારે મેં હજુલેખ હો જનરસાધારણ કો વિજ્ઞાપન કી મારી આકર્ષિત કરતો હો કે વિજ્ઞાપનાકારો સે વિજ્ઞાપન શુલ્ક કી વસૂલી કી જાયેગી કા કાર્ય નિયદિત કે માધ્યમ સે ઠેકે પર કિયા જાયેગા।

નગર પદ્ધાયત સીધાન્તર્વત સમ્બદ્ધિત નિય જાને વાલે ગ્લોસાઈન/સાઈન બોર્ડ જો દુકાનો કે નામ કે સાથ યા સ્વાચ્છ રૂપ સે કિસી વસ્તુ કે વિષય, ગુણ આદે કે બારે મેં હજુલેખ હો જનરસાધારણ કો વિજ્ઞાપન કી મારી આકર્ષિત કરતો હો કે વિજ્ઞાપનાકારો સે વિજ્ઞાપન શુલ્ક કી વસૂલી કી જાયેગી કા કાર્ય નિયદિત કે માધ્યમ સે ઠેકે પર કિયા જાયેગા।

વિજ્ઞાપન શુલ્ક કા મુગતાન પ્રતીક વિ નિય વર્ષ મેં 15 અન્ને તક મુંનીત અન્નિમ (100 પ્રતિશત) જમ કિયા જાયેગા। એક માણ તક શુલ્ક જમા ન હોસે પર સા બાંધેત વિજ્ઞાપન એજોન્સી કા પ્રોક્રિટ નિરસ્ત કરતે હું બ્લૈક લિસ્ટ કર દિય જાયેગા તથા બાકાયા વિજ્ઞાપન શુલ્ક કી વસૂલી મુ ગાપત્ર કી ગતિ વસૂલી કી જાયેગી।

શુલ્કની બોર્ડ યા અન્ય બોર્ડ જાહેર દોનોં ઔર વિજ્ઞાપન લિખો હોએ વસ્તો નિયારિન શુલ્ક દુનારો હો જાયોએ ઇન્ડિકેટર બોર્ડ કા સીઇજ 6 x 3 ફીટ સે અધિક કા નહીં હોએ।

વિજ્ઞાપન શુલ્ક નબાદ કે રૂપ મેં હો જાન કિયા જાયેગા।

નિયી નિય સે કી છતો પર વિજ્ઞાપન પટ્ટ દિયા। નગર પદ્ધાયત કી અન્નારી કે નહીં લનાયે જાયેગા।

પ્રત્યેક તિરાહો એવ ચીરાહે સે જાહેર કિ સમગ્ર-સમય પર વિજ્ઞાપન ૧ પટ્ટ એકદમ રાસ્તે કે કિનારે સે એક દૂસરે કે અગ્ર-બાગ્લ સે આને વાલે બાહોનો કા એક દૂસરે કો દૈખને મેં કલિનાઈ હોએ હૈ તથા ધાતાય ત મેં ગાંધી જાપન હોએ હૈ ઇન ચીરાહો એવ તિરાહો સે કેન્દ્ર સે ચારા ઔર પર્થી પર 25 મીટર તક વિજ્ઞાપન પટ્ટ લણાને મેં પ્રતિબન્ધ રહેણા।

પોલ ફિયોસ્ક કા સીઇજ 2 x 3 ફિટ હોએ।

રાંકાર દ્વારા સાધાર-સાધા પર પ્રતિબન્ધિત ઉત્પાદ્યો જેસે-સારાં તમારું ધ્યાપન એવ અસ્થીલ જાતિશ્વાક, ધર્મિક ભવનાનો મા જોંગેની કરન ગાલે પરં પૂર્ણ હિસલાન વિષયન ઉત્પાદ હાથેથાણે સે કાંઈમિત ઉત્પાદ રાખની વિજ્ઞાપન। એ પ્રદર્શન મુંનીત પ્રતિબન્ધિત રહેણા।

કિસી ની વિજ્ઞાપન એજો કી દુસરા ર ને રીક્ઓ પટ્ટ કે ઇતાર કોઇ વેદાપન પ્રતિબન્ધ કીયા હું ગાયા ગાયા તી નિય કેસી મોટ્રો કે વિજ્ઞાપન। એજોની કા પ્રોક્રિટ નિરસ્ત કર દિયા જાયેગા જીલ કે લિએ કર એવ રાજ્યદ અધોકાન ગુર એં એં તોત્ય કા સ્વીકૃત હોઈએ કા રાંકારાન નિયારિ રૂપ સે પ્રતિમાહ કરેણે

વિજ્ઞાપન કી સ્વીકૃતિ અધિકતમ એક વર્ષ કે લિએ હો જાયેગી।

નહિં અથવ ધાતાયત કી દૃષ્ટિ રે એ રાજ્ય રાંકાર કે નિર્માણ નું ર યદિ કિસી સ્વીકૃત વિજ્ઞાપન પટ્ટ કો હાનાને અનિરીક્ષણ હોએ હૈ તો બિન કિસી નોટિસ કે વિજ્ઞાપન પટ્ટ હાં દિયા જાયેગા, જિસ પર કોઇ પ્રાતોકર દેખ નહીં ત।

એ રોડ કાંચેર દ્વારા રોઇ શાડને (આઇઓઆરોફોનો) ૬૭ ૨૦૦૧ ને નિયારિત કલરો/માસ્ટો કા પ્રથી, હી વિજ્ઞાપન ૧ કે લેએ અનુભૂતિ હોએ, વિજ્ઞાપન પટ્ટો મેં પ્રથી જાને વાલે રા એન ફોન સાઇઝ ઓફિશિયલ ટૈકિફિ ૧ કે સાચાન એવ વાહન ચાલક કો પ્રગતિ કરતે વાલે નહીં હોએને।

ના પટ્ટ / યૂનિપોલ કા આવટન વિજ્ઞાપન શુલ્ક કે નિયારિત યૂનાન ધનરાશી પર સીલબન્ડ નિયદિતી આપન્નિત કર એ લોલીદ તા કો કિયા જાયેગા નિયદિતી મુખ્ય નાર એ વિકારી અથવા ઉનકે દ્વારા નાના તથિતી કે દ્વાર ખીંગી તથા ઉનકા નિર્ણય અનિતમ એવ માધ્ય હોએનું।

શ્રી નિયી મધ્ય એવ મૂભીય પર કિસી ગી પ્રકાર કે વિજ્ઞાપન ભવેધ રૂપ સે લાને પર વિજ્ઞાપન। એજો ની નેકેટસ ૧ રૂપાણી સે રૂ ૩૦ ૩૦૦૦ / મુખ્ય ૧ વસૂલ લોધી જાયેગ એવ અભેદ વિજ્ઞાપન પટ્ટ કો ૧.૫ાલ હટાતે દરે એજોની કા પ્રોક્રિટ એવ ટકા નિરસ્ત કર દિયા જાયેગા। ઇસ પર હાને વાલે વ્યય કે વસૂલી વિજ્ઞાપન એજોની એ સે કી જાયેગી।

નગર પદ્ધાયત મેં જીવીનું વિજ્ઞાપન એજેન્સીનો કો જો ભી વિજ્ઞાપન પટ્ટ સ્વીકૃત નિયે જાયેણે તું પર સુંદર સ્વચ્છ તિલવાદા કા રાંકાર પ્રદર્શિત નિયે જ એં તથા ધાતાયત કી દૃષ્ટિ સે પુરિસ્થ વેણા દ્વાર ખાંધી વિજ્ઞાપન કે લિએ હોએનું/યુનીપોલ મેં ઉનકી ઉંશકાન ગુસ્મર નિશ્ચિલ સ્થળ દિયા જાણો।

२९. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने विना किसी नोटिस के एजेन्सी वा पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

शासित

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम १९१८ की धारा २०३ (१) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹० ५००.०० तक हो सकेगा और जब ऐसा मौंग निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेतर जुमाना किया जायेगा जो प्रथम दोष रिक्षि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹० ५००.०० तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाडा(लद्दप्रयाग) में अन्तिम रूप में निहित होगा।

यह उप-नियमावधी नगर पंचायत हिलवाडा, जनपद- लद्दप्रयाग(उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहायि/विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत तिलवाडा।

मंगोल चिल्डयाल
आई.ए.एस
जिलाधिकारी, लद्दप्रयाग /
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाडा।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-रुद्रप्रयाग

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण

उपविधि-2018

०६ दिसम्बर, 2018 ई०

पत्रांक 413/न०प०तिं०(जप०गज०न००) / 2018-2019-

१- परिभाषा :

- (१) यह उपविधि नगर पंचायत तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) के ठेकेदारों को नियंत्रित एवं पंजीकरण उपविधि 2018-19 के हतायेगी तथा नगर में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।
- (२) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) से है
- (३) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) के निर्वाचित अध्यक्ष/समाचारों से है।
- (४) "अधिनियम" का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका परिषद अधिनियम १९१० (प०पी० स्थानिकियोंलिटी एवं ल०-२, १९१६ तथा संशोधित) जो कि वर्तमान में उत्तर खण्ड प्रदेश में भी लागू है-रो है।
- (५) "अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत, तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।
- (६) "अधिकारी" का तात्पर्य अधिकारी अधिकारी, नगर पंचायत, तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) से है
- (७) "पंजीकरण" का तात्पर्य नगर पंचायत द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के पंजीकरण से है
- (८) "ठेकेदार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति/ फर्म से है जो जो नगर नगर पंचायत तिलवाडा(रुद्रप्रयाग) में समस्त निर्माण कार्य, सड़क/नाली, निर्माण पुनर्निर्माण सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हों को करने का इच्छुक है।
- (९) "श्रेणी" का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ (A-B C.D) श्रेणी रो है।

१- पंजीकरण की प्रक्रिया :

नगर पंचायत/पालिका परिषद के सड़क/नालीपुस्ता एवं भवन के निर्माण कार्य के सम्बन्धमें एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की घार श्रेणीयां होनी इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय सूतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है -

- (१) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर सीमा जनपद या उत्तराखण्ड प्रदेश में कग तक कग से कग ५ वर्ष से नियास करता हो इसके लिए आवश्यक प्रगति-पत्र तथा दो पारापोर्ट साइज फोटो व जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह की अवधि के अन्दर का हा देने अनियार्य होगे
- (२) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है) -

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	-	25.00 लाख
(ख) द्वितीय श्रेणी के लिए	-	12.00 लाख
(ग) तृतीय श्रेणी के लिए	-	5.00 लाख
(ग) चतुर्थ श्रेणी के लिए	-	2.00 लाख

(३) प्रथम श्रेणी - प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग जल निगम, सिर्वार्ह विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग नगर पालिका एवं ग्रामीण पर्यायता अधिकारी विभागों में कम से कम सालक/गाली एवं भवन निर्माण का ६ वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में ₹ ५०.०० लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त स्वर्य की तकनीकी अभियन्ता एवं टी०एण्डपी० मिक्सचर मशीन एवं गाईवरेटर) आदि होने आवश्यक होंगे। (अनुभव प्राप्ति-पत्र अधिकारी/अधिकारी/अधिकारी/अधिकारी को अपर मुख्य अधिकारी को हस्ताक्षर से जारी किया गया भास्य होगा)।

(४) द्वितीय श्रेणी - द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम ३ वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में ₹ २०.०० लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे, (अनुभव प्रमाण-पत्र-अधिकारी/अधिकारी/अधिकारी/अधिकारी को अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया भास्य होगा)।

(५) तृतीय श्रेणी - तृतीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग गो का से कम से १ वर्ष का कार्य किया गया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।

(६) चतुर्थ श्रेणी - चतुर्थ श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखण्ड सरकार/सारांश सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम से एक वर्ष का कार्य किया गया हो का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।

(७) प्रत्येक ठेकेदार को आपकर व व्यापार के विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। तथा पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देना होगा तथा पंजीयन नम्बर के अग्रिमेद्य की छायाप्रति देनी होगी।

३- पंजीकरण की अवधि :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में माह ०१ अप्रैल से ३१ मई तक ही ठेकेदारों के पंजीकरण किये जा सकेंगे पंजीकरण के निर्धारित प्रार्थना पत्र के प्रारूप को ₹ २००.०० पंचायत कोष में जमा कर दिया करना होगा। तथा पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप पर मात्र होगा जो अवर अभियन्ता की आद्या पर अधिकारी/अधिकारी की संस्कृति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। तत्पश्चात ही पंजीकरण शुल्क एवं जमानत-शुल्क जमा किया जायेगा। पंजीकरण की वैधता १ अप्रैल से ३१ मार्च होगी।

४- जमानतें -

ठेकेदार को निभ श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बहत पत्र के रूप में अधिकारी/अधिकारी के पदनाम से बन्धक कर प्रार्थना-पत्र के साथ देनी होगी।

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	-	₹ ३०,०००.००
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	-	₹ २०,०००.००
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	-	₹ १२,०००.००
(द) चतुर्थ श्रेणी के लिए	-	₹ ८,०००.००

५- पंजीकरण शुल्क -

ठेकेदार को निभ श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नकद रूप में नगर परायता कोष में जमा करना होगा -

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए	-	₹ १५,०००.००
(ब) द्वितीय श्रेणी के लिए	-	₹ ८,०००.००
(स) तृतीय श्रेणी के लिए	-	₹ ४,०००.००
(द) चतुर्थ श्रेणी के लिए	-	₹ २,०००.००

6- नवीनीकरण ०

(1) अध्यक्ष / अधिकारी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उर के नुटिपूर्ण कार्य के कारण पंजीकरण / नवीनीकरण से रोका जा सकता है अथवा निरस्ता किया जा सकता है,

(2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्यक्षे ठेकेदार को निर्धारित प्रारूप पर आवदेन पत्र जिसका मूल्य ₹ 200.00 होगा नगर पंचायत कार्यालय से क्रय कर दिया जायें ये कार्यों का विवरण देना होगा ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार नवीनीकरण शुल्क नकद रूप में नगर पंचायत कोष में जमा करना होगा ०

(अ) प्रथम श्रेणी के लिए — ₹ 6,000.00
 (ब) द्वितीय श्रेणी के लिए — ₹ 4,000.00
 (स) तृतीय श्रेणी के लिए — ₹ 2,500.00
 (द) चतुर्थ श्रेणी के लिए — ₹ 1,500.00

7- निर्माण के सम्पादन की सीमा ०

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेप्डर लेने का अधिकार होगा ०

(1) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार रुपी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेप्डर लेने के अधिकारी होंगे।
 (2) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 25.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेप्डर लेने के अधिकारी होंगे।
 (3) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 10.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेप्डर लेने के अधिकारी होंगे।
 (4) चतुर्थ श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ₹ 4.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेप्डर लेने के अधिकारी होंगे।

8- निविदा प्रपत्र का मूल्य ०

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के बाय आयुगम (आयोगम) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा ०

क्र. सं.	कार्य की लागत (₹ में)	निविदा मूल्य (₹ में)
1	₹ 50,000.00 तक	200.00
2	₹ 50,001.00 से 2,00,000.00 तक	600.00
3	₹ 2,00,001.00 से 4,00,000.00 तक	800.00
4	₹ 4,00,001.00 से 20,00,000.00 तक	1500.00
5	₹ 20,00,001.00 से 50,00,000.00 तक	2500.00
6	₹ 50,00,001.00 से अधिक	4000.00

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य (वैर राहिल) देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का गूल्हा जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में न तो विस होगा और न ही आप्सी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किया जायेगा।

९ निविदा स्वीकार करने का अधिकार -

ठेकेदार द्वारा छाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/ अधिकारी अधिकारी का होगा परन्तु किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रशासक को होगा। इस दशा में पूँज निविदाये आमनित की जा सकती है। निविदा छालने के ८ माह बाद तक ठेकेदार उन्हीं पर्से पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

१०- धरोहर राशि -

निविदाये छालते साथ ३ प्रतिशत धरोहर धनराशि प्रत्रेक श्रेणी के ठेकेदारों का प्रतिशूति के रूप में जागा करनी आवश्यक है और यह प्रतिशूति आधेशासी अधिकारी के नाम बन्धक होगी। ऐसी प्रतिशूति को पूर्ण के कार्यों में जागा प्रतिशूति के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा, याक तक कि उन्हें अवगुवत नहीं किया गया हो।

११- ठेकेदार का भुगतान -

कार्य समाप्ति के द्वयात ठेकेदार को कार्य सन्तोषजनक होने पर निधानसार विल की धनराशि सं साध्य-समय पर निधारित दरों के भनुरार आयकर व्यापार कर साथलीं एवं जमानत की राशि काटते के उपरान्त कक्ष सामान्द के कार्य सन्तोषजनक प्रगाण गत्र पर भुगतान किया जा सकेगा, जमानत राशि का भुगतान १ वर्ष के बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अदर अधियनता की संस्तुति पर किया जा सकेगा।

१२- कार्य पूर्ण करने की अवधि -

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दिल्लि हो, कि वह टेक्स्टर फार्म में दो बहु कार्य अवधि १ अनुबन्ध पत्र (एपीम-८) के अन्वानत कार्य पूर्ण करे। यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाते हुए ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औद्योगिक स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया हो तो अदर अधियनता एवं अधिकारी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवश्य कार्य पर उत्तराल्पाठ आधिकारि नियम वली २००४ नि. १ द्वारा प्रत्याना के भनुरार अधिकारि स्वस्त्र कठोरी कर ली जायेगी यदि इस धनराशि को प्रतिशूति विल की धनसाशी से नहीं हो पते की विधि में दप्त की अवश्य धनराशि की वर्गीकृती भू-राजरन के बकाये जी भाति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी, इसका उल्लेख अनुबन्धनामे में भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

१३- पंजीकरण निरस्तीकरण -

यदि ठेकेदार निधारित विधि तक कार्य प्रारंभ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक भुगतान के अनुसार स्वीकृत व साइ. लून के अनुसूप नहीं करता है तो कार्य को किसी को सबलेट करता है तो ऐसी स्थिति में समानाद अदर अधियनता एवं अधिकारी अधिकारी की जाव आख्या/ संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को किसी भी समय निरस्ता कर ठेकेदार को काली सूची में लाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजीकृत ठेकेदार के विरुद्ध जीव गे जमा किया गया काई भी अभिलेख अनुभव प्रमाण पत्र गा उन्हें दस्तावेज यदि फर्जी पाये जाते हैं तो सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण निरस्ता कर किये जाने के उपरान्त प्रथम सून। रिपोर्ट (।११, इजी करता ही जायेगी। पंजीकरण के निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का तेजा रूपत ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का भुगतान प्रयाप्ति को दुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा। इसका उल्लेख अनुबन्धनामे में भी किया जायेगा।

* 14- जमानत जीव्त करने का अधिकार ~

यदि ठेकेदार नगर पंचायत उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध-पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुंचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या / संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त करने, ठेकेदार को काली सूची गे समिलित कर ठेकेदार की जमानत जीव्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकाये की भूमि व्यापूल की जायेगी, इसका उल्लेख अनुबन्धनाम में भी किया जायेगा।

यह उप-नियमावली नगर पंचायत तिलवाडा, जनपद-लद्दप्रयाग(उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहमति/स्वीकृति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाडा,
जनपद-लद्दप्रयाग।

मंगेश धिरिंद्रियाल,
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, लद्दप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाडा।

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद रुद्रप्रयाग

प्लास्टिक अवशेष (कचरा) प्रबन्धन एवं व्यवहार आदर्श

उप नियमावली-2018

०८ दिसम्बर, २०१८ ई०

पत्रांक ४१३/न०प०तिं०(चप०गज०न००)/२०१८-२०१९-

१- उपनियम

(१) संक्षिप्त आगम एवं उत्पत्ति पर्यावरण (संरक्षण) एकट १९८६ के अन्तर्गत प्लास्टिक कचरा अवशेष (प्रबन्धन एवं व्यवहार)नियमावली-२०११ के नियम ४ (बी) के अन्तर्गत दी गई शक्तिग्रों के अधीन नगर पंचायत तिलवाडा (रुद्रप्रयाग) इस एकट के आधार पर रक्षम अधिकारी के तौर पर प्लास्टिक कचरे का प्रयोग एकत्रीकरण, छाई उठान, निस्तारण व पुनर्नियन्त्रण के लिए उपयुक्त विधायी शक्तिग्रों का निर्वहन करेगी। उपयुक्त के अन्तर्गत नियमावली निम्न प्रकार होगी

२- परिमाण :

- (१) "कैरी बैग" का अर्थ प्लास्टिक वी थैलिया जिन्हे उपयोग सामग्री के लिए प्रयोग में लाया जाता हो जिसमें स्वतं ले जाने योग्य लक्षण हो सहित
- (२) "कालरेन्टस्" ये रगने वाले पदार्थ जो भारतीय प्रमाणिकता आई०प्रा० ९८३३.१९८१ की अनुसार निर्धारित हों।
- (३) "एकत्रीकरण" का अर्थ प्लास्टिक कचरे को स्थायी एकत्रीकरण स्थल से छाया, अन्य किसी स्थान से उठाना व हटाना
- (४) "एकत्रीकरण स्थल" का अर्थ वह निर्धारित स्थान शेष किशोर या छावा जो स्थूनिसिपल या सरकारी जमीन, अधिकारी सावजनिक स्थान जहां प्लास्टिक कचरा प्राप्त करना व हटाना शामिल है।
- (५) "सामग्री" का अर्थ शाक संबंधित फल, दवाईयाँ, खाद्य सामग्री तथा इसी प्रकार की वस्तुएँ साथ ही अन्य किसी भी प्रकार की वस्तुएँ।
- (६) "कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक" का अर्थ यह है कि प्लास्टिक जो जैविक प्रक्रिय से कम्पोस्टिंग के दौरान C₀₂ (कार्बन डाइआव्साइड) पानी जैविक पदार्थों तथा व्यायोमास के सम्पर्क के दौरान अन्य सात कम्पोस्ट योग्य पदार्थों के भाति अनुकूल रहता है तथा कोई दूष्यगाम अन्तर दर्शाने वाले तथा सायनिक अवशेष नहीं छोड़ता है।

(7) “પૃથ્વીકીરણ” કા અર્થ યહ હૈ કિ પદાર્થોની છોટે છોટે હિસ્સાની મેળે બાંને કી પ્રક્રિયા ।

(8) “પર્યાવરણ” કા અર્થ ઉન મૌલિક વ પરિસ્થિતિકી સે સમ્બન્ધિત હૈ જો જીવોની જીવન કે વિકાસ કો પ્રભાવિત કરતા હૈ

(9) “ઉત્પાદક કી વિરતારિત જિમ્મેદારી”(EPR) કા અર્થ હૈ કિ પ્લાસ્ટિક કેરી બેગ તથા બહુસ્તરીય પ્લાસ્ટિક થૈલિયો કી પૈકિંગ સામગ્રી કે ઉત્પાદક યા નિર્માતા કી વહ જિમ્મેદારી જિસકે અન્તર્ગત નિર્મિત પ્લાસ્ટિક સામગ્રી કે સમાપ્ત હોને તથ સામગ્રી કા પર્યાવરણીય પ્રસંગીકરણ સુનિશ્ચિત હો યહ જિમ્મેદારી ઉન સાથી નિર્માણાંત્રો પર ભી લાગુ હોતી હૈ જો ઇસ પ્રકાર કી પૈકિંગ સામગ્રી કા ઉપયોગ કરતે હોય ।

(10) “ખાદ્ય સામગ્રી” કા અર્થ વહ સામગ્રી જો દ્રવ્ય, ઠોસ વ ઠોસ જૈસી રૂપોને ગે તુરન્ત ખાને યોગ્ય પદાર્થ ફાસ્ટ ફૂડ પ્રરારકૃત યા બને હુએ ભોજન કે રૂપ મેળે હો

(11) “નિર્માતા” કા અર્થ હૈ વહ અંગીત યા સરસ્યા જો પ્લાસ્ટિક કેરી બેગ, બહુસ્તરીય પૈકિંગ સામગ્રી પાણી તથા યા હસ્તી પ્રકાર કી સામગ્રી કી પૈકિંગ કે લિએ ઉત્પાદન કરતા હો ।

(12) “માદ્યાંક્રોન” કા અર્થ હૈ પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ કે ભાપન કી ઇન્ગેન જો એક મિલીમીટર કે દશાવેં હિસ્સો કે બરાબર હો

(13) “બહુસ્તરીય પ્લાસ્ટિક” કા અર્થ હૈ વહ સામગ્રી જો પૈકિંગ હેતુ કર્હી સ્તરો જૈસે કાગજ, ગત્તો પાલીમર સામગ્રી યા એલ્યુગીનિયમ ફાયલ કી પરસ્યુક્ત યા સામાન્યિત રૂપ મેળે હો ।

(14) “પિગમેન્ટ” કા અર્થ હૈ એક રંગયુક્ત પદાર્થ અથવા તત્ત્વ હૈ ।

(15) “પ્લાસ્ટિક” કા અર્થ વહ પદાર્થ જિસમે ઉચ્ચ પાલીમર કે સત્ત્વ વિદ્યામાન હોય તથા જો ઉસમે પ્રસંસ્કરણ પ્રક્રિયા મેળે અન્તિમ સામગ્રી કે રૂપ મેળે અપને સ્વામાનિક રૂપ મેળે રહે

(16) “પ્લાસ્ટિક કાચસ” કા અર્થ કોર્ઝ પ્લાસ્ટિક કાચસ જો કેરી બેગ, પાણી તથા બહુસ્તરીય પૈકિંગ સામગ્રી કે રૂપ મેળે ઉપયોગ કીયા જાએ વ જિસે ઉપયોગ કે ઉપરાન્ત અથવા ઉનકી જીવનકાળ કે ઉપરાન્ત ફેંક દિયા જાએ ।

(17) “પ્રરાસ્કરણ” કા અર્થ કોર્ઝ વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા જિસમે પ્લાસ્ટિક કાચરે કો ઉપદ્યારિત કર પુને ઉપયોગ હેતુ બનાયા જા સકે ।

(१८) “पुनर्वक्रीकरण” का अर्थ पृथकीकरण अजैविक प्लास्टिक कचरे को परिवर्तन प्रक्रिया के आधार पर नये उत्पाद के कच्चे माल के रूप में तैयार किया जाए जो अपने मौलिक रूप में हों अथवा नहीं।

(१९) “पुनर्वक्रीकृत बैग” का अर्थ वह बैग जो उपयोग किये गये पालीमर या पूर्ववत् प्रसरित प्लास्टिक से बना हो,

(२०) “पृथकीकरण” का अर्थ वह म्यूनिसिपल टोस कचरा जो जैविक व अजैविक कचरे खतरनाक विकित्सकीय, सूक्ष्म कचरा, निर्माण व तोड़ने से निकलने वाले कचरे, बाग व बगीचों का कचरा, तथा सभी लशह के कचरे

(२१) “दुलान” का अर्थ म्यूनिसिपल कचरे का एक स्थान से दूसरे स्थान तक लै जाना,

(२२) “वर्जिन प्लास्टिक” का अर्थ वह प्लास्टिक जो पूर्व में उपयोग में नहीं लाई गयी हो अथवा किसी कचरे या अवशेष के साथ मिलाया न गया हो

(२३) “अवशिष्ट प्रबन्धन” का अर्थ वैज्ञानिक आधार पर कम करना द्वारा उपयोग, पुनर्वक्रीयण, कम्पोस्टिंग या प्लास्टिक कचरे का निःसारण,

(२४) “लैरेट पिकर” का अर्थ उन लोगों से है जो अकेले या समुदाय में रहकर प्लास्टिक अवशिष्ट का एकत्रीकरण करते हैं।

३— कैरी बैग तथा छोटे पाऊच आदि के स्तरक, वितरण, विक्रय हेतु निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक :

(१) कैरी बैग प्राकृतिक रंग (रंग रहित) जिसमें कोई रंग तत्व न हो या भारतीय प्रथापूर्णता, आई एस १९८३-१९८१ के अनुसार वैधानिक रंग तथा द्वारा निर्भित हो।

(२) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे कैरी बैग जो पुनर्वक्रित प्लास्टिक या कम्पोस्ट किये जाने वाले प्लास्टिक से बने हों, को खाद्य पदार्थों के स्टोर लाने ते जाने विवरण या पैकिंग के लिए प्रयोग में लाया जाए।

(३) किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी कैरी बैग का उत्पादन स्टोर वितरण या विक्री नहीं किया जा सकता है जो ४० माइक्रोन की मोटाई से कम हो या वर्जिन पुनर्वक्रीकरण या कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक से न बना हो।

(क) कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक वह जो मार्तीय प्रमाणिकता आई०एस०/आई०एस०ओ० १७०८८ जो समय समय पर संशोधन के आधार पर कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक के लिए निर्धारित किये गये हैं।

४— प्लास्टिक कचरा प्रबन्धन निम्नानुसार हो ।

(अ) प्लास्टिक कचरे का पुनर्द्यक्षण, पुन ग्राप्त करना, निस्तारण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों प्रावधानों व प्रमाणिकता के अनुसार किया जाना होगा

(इ) नगर पंचायत, तिलाडा (ज़द्दप्रधान) कचरा प्रबन्धन के संचालन तथा समन्वयन के लिए निम्न सम्बद्ध गतिविधियाँ संधालित करेंगे

(ii) प्लास्टिक कचरे का सुरक्षित एकत्रीकरण स्टोर पृथकीकरण, दुलान, प्रसरकरण तथा निस्तारण ।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि प्रसरकरण के दौरान पर्यावरण को किसी भी प्रकार कश नुकसान न हो ।

(iv) यह सुनिश्चित करना कि यदि सम्बद्ध हो तो प्लास्टिक कचरे के एकत्रीकरण केन्द्र के निर्माण में निर्माता को भागीदार बनाना ।

(v) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक कचरे को पुनर्द्यक्षण करने वाली संस्थाओं के साथ निरन्तरता स्थापित करना ।

(vi) जागृति कार्यक्रमों से इससे जुले सभी सम्बद्ध इकाईयों को उनकी जिम्मेदारियों का ज्ञान बढाना ।

(vii) कचरा प्रबन्धन में जुड़ी सभी संस्थाओं या समूहों(कूड़ा बीनने वालों सहित) को जोड़ना ।

(viii) यह सुनिश्चित करना कि प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाना ।

(ix) यह कि एकत्रीकरण व्यवस्था की जिम्मेदारी म्यूनिसपेलिटी की है तथा इस उद्देश्य के लिए वह प्लास्टिक कैंसी बैग बहु स्तरीय प्लास्टिक पाउच या थीलिया प्लास्टिक बोतलें, प्लास्टिक तिरपाल शीतल पेय वस्तुएँ आदि के निर्माताओं या ब्राउ मालिक जो इनका उपयोग करते हैं की सहायता ले सकती है ।

(i) यह म्यूनिसपेलिटी प्लास्टिक कचरे के विस्क्रमण के लिए श्रीनगर विस्क्रमण व परतीकरण इकाई जो उत्तराखण्ड टूरिज्म डेवलपमेन्ट बोर्ड

द्वारा संचलित है तथा गढ़वाल रेज के शहरी स्थानिक संस्थाओं के विकास के लिए है तथा प्लास्टिक प्रसंस्करण व पुनर्व्युत्पादन इकाइ काठगोदाम जो झील विकास प्रधिकरण नैनीताल द्वारा कुमाऊ क्षेत्र के शहरी स्थानिक संस्थाओं हेतु बलाई जा रही है। के साथ समन्वय करेगी।

5. विषयन या चिन्हिकरण हेतु प्रयास :

(1) प्रत्येक प्लास्टिक कैरी बैग का बहुस्तरीय पाऊच या थैली में निम्न सूचना अंग्रेजी या स्थानीय भाषा में प्रिंट करना आवश्यक होगा।

(i) निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संस्था तथा कैरी बैग की स्थिति में उसकी मोटाई।

(ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाऊच वा थैली में निर्माता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या

(iii) सभी पुनर्व्युत्पादन कैरी बैग में "पुनर्व्युत्पादन" लिखा हुआ या चिन्हित हो जो भारतीय प्रामाणिकता : आईएसो 14534 1998 के अनुसार निर्भित हो।

(iv) सभी वे धैरी बैग जो कम्पोस्ट योग्य प्लास्टिक हों में कम्पोस्ट योग्य लिखा हुआ या चिन्हित हो तथा भारतीय प्रामाणिकता के अनुसार निर्भित हो

(v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय पाऊच या थैलियां जो उनके द्वारा बेचे जाएं में नियमानुसार चिन्हित हों।

6- इसके अतिरिक्त कोई भी कैरी बैग खुदरा व्यापारियों द्वारा क्रेताओं को निशुल्क उपलब्ध नहीं होना चाहिए कैरी बैग का न्यूनतम गूल्य कैरी बैग की गुणवत्ता व आकार के अनुसार हों जो उसके निर्गमन सम्भवी तथा कचरा प्रबन्धन की लागत भी शामिल हो पिससे प्लास्टिक कचरा सबर्धन में कमी करने को बढ़ावा दिया जा सके कैरी बैग की कीमत जो क्रेताओं से ली जाए ₹ 1/- से कम न हो।

7- इसके अतिरिक्त म्यूनिसप्लिटी समय-समय पर जब भी आवश्यकता हो जाँच कर सकेंगी।

8- यूपी० प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक कूड़े(उपयोग का विधान व निस्तारण) एकट 2000 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा फैके गये अजैविक बैग या डिब्बा के द्वारा निन स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं

- (i) नालियों व सीवर लाइन व्यवस्था में व्यवधान पैदा होना।
- (ii) नालियों व सीवर के उदामदों की निरन्तरता व निस्तारण व उपचार में व्यवधान उत्पन्न होना।
- (iii) जैन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक व लोक कन्टक का कारण हो सकता है।
- (iv) मूनिसपेलिटी क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय सौन्दर्य के लिए खतरा या नुकसान का कारण बन सकता है।
- (v) सभी खुदरा व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी प्लास्टिक कैरी बैग तथा बहुस्तरीय पाउच या थैलिया जो उनके द्वारा बेचे जाएं, में नियमानुसार थिन्हिल हों।

उक्त सभी खतरों के लिए एक नियमावली के प्रावधान संख्या ८, के अनुसार दण्डनीय अपशाद है। उसी के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यह उप-नियमावली नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-लद्दप्रयाग(उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहमति/स्वीकृति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविशंज सिंह बंगारी,
अधिकारी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाडा,
जनपद-लद्दप्रयाग

मंगेश घिल्डमाल,
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, लद्दप्रयाग /
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाडा

कार्यालय नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-खद्दप्रयाग
लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह

उपविधि-2018

०६ दिसम्बर, २०१८ ई०

पत्रांक ४१३/न०प०ति०(उप०यज०न००) /२०१८-२०१९-

- १- यह उपविधि नगर पंचायत, तिलवाडा जनपद-खद्दप्रयाग (उत्तराखण्ड) के सीमान्तर्गत विभिन्न एवं निजी स्तर से संचालित व्यवसायों पर लागू होगी एवं यह उपविधि लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि, सन् २०१८ कहलायेगी।
- २- प्रसिद्धान्वय नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत तिलवाडा जनपद-खद्दप्रयाग से है।
 - (१) “अधिनियम” का तात्पर्य उ०प्र० नगर पालिका परिषद अधिनियम १९१६ (यथा संशोधित य०पी० मूलनियमप्रेलिटी एक्ट १९१६) जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश से भी लागू है—से है।
 - (२) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत तिलवाडा(खद्दप्रयाग) के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।
 - (३) “अधिशासी अधिकारी” का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, तिलवाडा(खद्दप्रयाग) से है।
 - (४) “लाइसेंस” से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा २९४ व २९८ की उपधारा (२) के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण व्यवसायों उपविधियों के उधीन उल्लिखित एवं विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत अनुसूची में वर्णित व्यवस्था व दरों से है तथा विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु दी जाने वाली स्थीकृति से है।
 - (५) “आवधि” लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए १ मध्येल से ३१ मार्च तक होगी लाइसेंस वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी किया जाए लाइसेंस अवधि ३१ मार्च को समाप्त हो जायेगी।
 - (६) “अनुसूची” से तात्पर्य इस उपविधि में वर्णित व्यवसायों एवं लाइसेंस शुल्क की दरों से है।

(7) यदि कोई व्यवसाय एक से अधिक वर्गीकृत व्यवसाय श्रेणी मे नाना जा सकता हो तो अनुसूची मे जिस श्रेणी मद पर अधिक दर से लाइसेन्स शुल्क निहित किया गया हो उसी के अनुसार उस व्यवसाय पर लाइसेन्स शुल्क लगाया व वसूला जायेगा

(8) व्यवसाय से सम्बन्धित श्रेणी/ विवरण (मद) के सम्बन्ध मे अधिशासी अधिकारी का निर्णय अनित्तम व मान्य होगा।

3- लाइसेन्स आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) देनी होगी तथा आवेदन मे व्यवसाय / विवरण का उल्लेख भी करना होगा।

4- पापा आवेदन पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित विचारोपरान्त लाइसेन्स दिये जाने / न दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा न दिये जाने की सूचना का कारण भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

5- अनुसूची मे वर्गीकृत व्यवसायों से सम्बन्धित व्यवसाय द्वारा लाइसेन्स 1 अप्रैल से 31 गई तारीख की अवधि के भीतर बना लिया जाना अनिवार्य होगा।

6- लाइसेन्स की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च (1 वित्तीय वर्ष) तक वैध होगा अन्यथा रिस्ति मे विलम्ब शुल्क (जो लाइसेन्स शुल्क का 10 प्रतिशत से कम न होगा), लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा व अधिकृत अधिभार के रूप मे जगा करन स्वीकृत होगा।

7- लाइसेन्स धारक अपना व्यवसाय यदि बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक भाष्य के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय मे अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप से उपलब्ध करायेगा।

8- लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अधिकारी मे निहित होगा।

9- जांचकर्ता की जांच के समय व्यवसाय से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसायी का होगा।

10- लाइसेन्स अधिकारी स्वयं अथवा अपने ऐजेन्सी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है।

11- उक्त अनुसूची मे वर्गीकृत लाइसेन्स सम्बन्धी नियम- उपनियमो का उल्लंघन होने अथवा पाये जाने की दशा मे लाइसेन्स अधिकारी जनहित मे किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है ऐसी रिस्ति मे लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरुद्ध काई भी अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष मे निहित होगा।

12- नगर पंचायत तिलवाडा उनपद- रुद्रप्रयाग ने इन उपविधियो/नियम उपनियमो के तहत वर्तमान मे प्रचलित विभिन्न लाइसेन्स उपविधिया उस सीमा तक, जो इस नियमावली के लिए असंगत होगी, वे निरस्त समझी जायेगी।

13. विवरण विषयों के सम्बन्ध में इन उपविधियों में कोई उप नियम नहीं होगे उन विषयों में अधिशासी अधिकारी स्वयंविवेक अनुसार निर्णय ले सकता है ऐसा निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14. अधिशासी अधिकारी समय-समय पर ऐसे प्रपत्र भी निहित कर सकता है जो इन उपविधियों के सम्बन्ध पालन के लिए आवश्यक हो।

अनुसूची

क्र. सं	विवरण (मद)	निर्धारित दरें
1	होटल लॉज 10 बैड रैक	1000.00
2	होटल लॉज बैड 10 बैड से अधिक	2000.00
3	गेस्ट हाउस	100.00
4	रेस्टोरेंट	1000.00
5	नॉर्सिंग होम	5000.00
6	पैथोलॉजी सेंटर	500.00
7	एम्स रे सेंटर	2000.00
8	डेंटल क्लीनिक	500.00
9	मेडिकल स्टोर	2000.00
10	मोटर गैरेज	800.00
11	स्कूटर गैरेज / शिपियरिंग शाप	600.00
12	पेट्रोल पंप/डीजल पंप आयल कंपनी	5000.00
13	बचकी	600.00
14	ड्राइवलीनर	1000.00
15	फर्मीचर की निमति /	200.00
16	फर्मीचर शोरूम/दुकान	2500.00
17	हाउवेयर/लॉहा व्यापारी सीमेंट, इंट	4500.00
18	बिजली के सामान की दुकान	800.00
19	कपड़ा व्यापारी/कपड़े की दुकान	1500.00
20	टेट एवं कैटरिंग	1500.00
21	बैकरी (भट्टी)	1000.00
22	बैकरी (बिजली)	500.00
23	ब्यूटी पालर	1500.00
24	कुकिंग गैस ऐरोसी	5000.00
25	जनरल भर्चैन्ट	800.00
26	टेलरिंग हाऊस 1 मशीन	300.00
27	टेलरिंग हाऊस 3 मशीन लैक	700.00
28	टेलरिंग हाऊस 3 से अधिक	1000.00
29	जैवलस	4000.00
30	डेयरी	600.00
31	कैबिल नेटवर्क	1000.00
32	आडियो एवं वीडियो लाइब्रेरी	800.00
33	एकाउन्टेट कन्सलटेट आदि	2000.00

34	फाइनेंस कम्पनी, चिटफॉड आदि	3500.00
35	इन्योरेश कम्पनी प्रति शाखा	4500.00
36	मांस विक्रेता(बकरा/मुर्गा)	2000.00
37	बिदेशी शराब की दुकान	25000.00
38	पान की दुकान	600.00
39	चाय की दुकान	600.00
40	किताबों की दुकान स्टेशनरी	1500.00
41	लकड़ी का टाल	1000.00
42	रेडियो /टीवी/ धड़ी /मोबाइल रिपेयरिंग	600.00
43	रेडियो /टीवी/ मोबाइल की दुकान /शो रूम	2000.00
44	वर्तन/क्राकरी/प्लास्टिक सामान की दुकान	500.00
45	गिटाई की दुकान	1000.00
46	बाट/बताशा/ की दुकान	500.00
47	सब्जी और फल की दुकान छोटी	800.00
48	सब्जी और फल की दुकान बड़ी थोक	2000.00
49	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	3000.00
50	धूड़ी/कार्सीटिक आदि	000.00
51	फोटोग्राफर	700.00
52	बारातघर	5000.00
53	प्राह्वेट रेस्ट	3500.00
54	रेडिमेंट गारमेंट्स	1800.00
55	कड़ाड़ी	2500.00
56	कम्प्यूटर कोड़िंग	2500.00
57	कम्प्यूटर जाब वर्क	1000.00
58	रेपर पार्ट्स की दुकान	800.00
59	खाने का होटल	800.00
60	डाका	800.00
61	डेयर ब्लैसर	000.00
62	आर्टिकल्स	700.00
63	वाहन शोरूम(सोल्सा सर्विस)	4000.00
64	परघून	1200.00

यह उप-नियमादली नगर पंचायत, तिलवाडा, जनपद-लद्धप्रयाग(उत्तराखण्ड) के प्रशासक की सहमति/स्वीकृति से विशेष प्रस्ताव के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाडा,
जनपद-लद्धप्रयाग।

मंगेश घिल्डयाल
आई.ए.एस.
जिलाधिकारी, लद्धप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाडा

કાર્યાલય નગર પંચાયત, તિલવાડા જનપદ—રૂદ્રપ્રયાગ

નગરીય ઠોસ અપશિષ્ટ પ્રબન્ધન ઉપવિધિ—2018

06 દિસેમ્બર, 2018 ઈ0

પત્રાંક 413/નોયોટિ૦(ઉપોગ્રાનો૦)/2018-2018—

સંક્ષિપ્ત પ્રસાર એવ પ્રારંભઃ—

1. યહ ઉપવિધિ નગર પંચાયત, તિલવાડા કી 'નગરીય ઠોસ અપશિષ્ટ પ્રબન્ધન ઉપવિધિ, "2018" કહાલાયેગી।
2. યહ ઉપવિધિ નગર પંચાયત, તિલવાડા કી સામસ્ત ક્ષેત્રો મેં પ્રમાણી હોયોએ।
3. યહ ઉપવિધિ સરકારી ગ્રાન્ટ ઉત્તરાખંડ મેં પ્રકાશન કી તિથિ સે પ્રમાણી હોયોએ।
4. પરિમાણોને—

- a) "ઉપવિધિ" સે તાત્પર્ય નગર પાલિકા અધિનિયમ 1918 કે ઉપબન્ધોને અધીન ઇનાર્ઝ ગઈ કોઈ ઉપવિધિ સે હૈ।
- b) "અધ્યક્ષ" કો સાત્પર્ય નગર પંચાયત, તિલવાડા કો અધ્યક્ષ/પ્રશાસક સે હૈ।
- c) "કોર્ડ" કો સાત્પર્ય નગર પંચાયત, તિલવાડા કે નિર્ધારિત અધ્યક્ષ/સદ્વસ્તો અથવા પ્રશાસક સે હૈ।
- d) "અધિનિયમ" કો સાત્પર્ય ઉત્તર પ્રદેશ નગર પાલિકા અધિનિયમ-1918 (ઉત્તરાખંડ મેં યથાપ્રવૃત્ત) સંશોધન એવ ઉપાન્તરણ કરાદેશ-2002 સે હૈ।
- e) "નગર પંચાયત" સે 'સાત્પર્ય નગર પંચાયત, તિલવાડા સે હૈ।
- f) "અધિશાસી અધિકારી" સે સાત્પર્ય અધિશાસી અધિકારી નગર નગર તિલવાડા સે હૈ।
- g) "સફાઈ નિરીક્ષક" સે સાત્પર્ય નગર પંચાયત, તિલવાડા (રૂદ્રપ્રયાગ) મેં હાસન દ્વારા રૈનાનુસાર સફાઈ નિરીક્ષક સે હૈ। એસે અધિકારી કે ઉપલબ્ધ ન હોને કી સિદ્ધાંતે મેં નગર પાલિકા/નગર પંચાયત કે ઉસ અધિકારી/કર્મચારી સે હૈ જો ઉસ દદ કે કાર્યાલાર કે લિએ બાસન યા પ્રશાસક યા અધિશાસી અધિકારી દ્વારા અધિકૃત કીયા ગયા હો।
- h) "નિરીક્ષક અધિકારી" કો સાત્પર્ય સુચય અધિશાસી અધિકારી નગર સ્વારથ્ય અધિકારી, સફાઈ નિરીક્ષક અથવા એસે અધિકારી/કર્મચારી સે હૈ જિન્હે સમય-સમય પર અધિશાસી અધિકારી કે આદેશ નિરીક્ષણ કે લિયે અધિકૃત કીયા ગયા હો।
- i) "નિયમ" સે સાત્પર્ય ભારત સરકાર કે પર્યાવરણ ઔર વન મંત્રાલય કી અધિસૂચના રૂં ૮૫૫ નઈ દિલ્હી, મંગલવાર ૦૩ અક્ટૂબર, ૨૦૦૦ અન્નાધારણ અધિસૂચના નઈ દિલ્હી, દિનાંક ૨૫ સિસ્ટમ્બર, ૨૦૦૦ કે દ્વારા પર્યાવરણ (સરકાર) અધિનિયમ, ૧૯૯૯ કે અન્તર્ગત નગરીય ઠોસ (પ્રબન્ધન એવ હથાલાન) નિયમ, ૨૦૦૦ વ પર્યાવરણ વન ઔર જલવાયુ મંત્રાલય કી અધિસૂચના રૂં ૮૬૧ નઈ દિલ્હી, શુક્રવાર અપ્રેલ, ૮, ૨૦૧૬ બાયે ગયે ઠોસ અપશિષ્ટ પ્રબન્ધન નિયમ, ૨૦૧૬ વ અધિસૂચના રૂં ૧૯૭ દિનાંક ૨૮ માર્ચ, ૨૦૧૬ સે હૈ।
- j) "અધિનિયમ" સે સાત્પર્ય ઉત્તર પ્રદેશ/ઉત્તરાખંડ, નગર પાલિકા અધિનિયમ સે હૈ।
- k) "જીવ નાશિત/જીવ નિમ્નકરણ અપશિષ્ટ" (Biodegradable waste) સે સાત્પર્ય એસે અપશિષ્ટ સે જિસકા સૂહમ જીવો દ્વારા નિમ્નકરણ કીયા જા સકતા હૈ જીસે-બચા હુઆ ખાના સબ્જી-ફલ કે છિલકે ફૂલ-પીંઠો કે પત્તે આદી।
- l) "જીવ અનાશિત અપશિષ્ટ" (Non-Biodegradable waste) કો સાત્પર્ય એસે કૂડા-કદરા જામદ્રો સે હૈ, જો જીવ નાશિત કૂડા-કદરા નહીં હૈ ઔર ઇસકે અન્તર્ગત પ્લાસ્ટિક બી હૈ।
- m) "પુનર્દ્રાગણીય અપશિષ્ટ" (Recyclable waste) સે સાત્પર્ય એસે અપશિષ્ટ સે હૈ જો દુષ્કાર કિસી ભી પ્રકાર સીધે અથવા કિસી વિધિ સે પરિવર્તન ઉપરાંત પ્રયોગ મેં આ સકતા હો જીરો-પ્લાસ્ટિક, પોલિથીન, કાગજ, ધાતુ, રબડ આદી।
- n) "જીવધ્રીકિતસીય અપશિષ્ટ" (Biomedical waste) સે સાત્પર્ય એસે અપશિષ્ટ સે હૈ, જિસકા જનન માન્યો એ પણું કે નિદાન, ઉપચાર યા પ્રાસીકરણ કે દીશન મુશ્કે હૈ।
- o) "સેંગ્રહણ" (Collection) સે સાત્પર્ય અપશિષ્ટ કે ઉત્પત્તિ સ્થળ સેંગ્રહણ બિન્ડુઓ તથા કિસી અન્ય સ્થળ સે ઠોસ અપશિષ્ટ કો ઉઠાયા જાના અભિપ્રેત હૈ।
- p) "કદરા ખાદ બનાને" (Composting) સે એક એસી નિર્ધારિત પ્રક્રિયા અભિપ્રેત હૈ જિસમે કાર્બનિક પદાર્થ કા સૂહમ જીવીય નિમ્નકરણ અન્તર્વિલિત હૈ।
- q) "ભાન તથા નિર્માણ સમબન્ધી અપશિષ્ટ" (Demolition and Construction Waste) સે સન્મિનાણ, પુન નિર્માણ, મરમાત ઔર ભાનને સમબન્ધી સંક્રિયા કે પરિણામસ્વરૂપ નિર્માણ જામદ્રો રોઝિયો ઔર મલબે સે ઉદ્ભૂતઅપશિષ્ટ અભિપ્રેત હૈ।
- r) "દ્વારા" (Disposal) સે ભૂજલ સત્તાની જલ તથા પરિવર્તી વાયુ યુણતા કો સન્દૂધણ સે બચાને હેતુ આપશ્યક સાધારણી સે નગરીય ઠોસ અપશિષ્ટ કો અન્તિમ રૂપ સે દ્વારા અભિપ્રેત હૈ।
- s) "અપશિષ્ટોની ઉત્પાદક" (Generator of Waste) સે નગરીય ઠોસ અપશિષ્ટ કો ઉત્પાદન કરને વાલે દ્વારા યા સ્થાપન અભિપ્રેત હૈ।
- t) "ભૂમિસરણ" (Landfilling) સે ભૂજલ સત્તાની જલ કા પ્રદૂષણ ઔર વાયુ કે જાથ ઉઠને વાલે બૂલ હ્યા કે સાથ ઉઠને વાલા બદનુ આગ કે ખતરે, પણીયો કા ખતરા નાશી જીવ/કૃત્તક ગ્રીન હાઉસ ગૈસ ઉત્સર્જન ઢાલ અસ્થિરતા ઔર કટાવ કે લિએ સંરક્ષાત્મક ચસ્પર્યો કે સાથ ડિઝાઇન કી ગઈ સુવિદા મેં અપશિષ્ટ ઠોસ અપશિષ્ટ કા ભૂમિસરણ પર નિપાટાન અભિપ્રેત હૈ।
- u) "નિકાલિતક" (Leachate) સે વહ દ્વારા અભિપ્રેત હૈ જિસકા ઠોસ અપશિષ્ટ યા અન્ય માધ્યમ સે રિસાવ હુયા હૈ તથા જિસને ઇસમે સે ઘુલિત અથવા નિલમ્બિત પદાર્થ કુ નિષ્કર્ષણ કીયા હૈ।

v) "नगर पालिका प्राधिकारी" (Municipal Authority) से मुनिशिपल कार्पोरेशन, मुनिशिपलीटी, नगर पालिका, नगर पंचायत नियमके अन्तर्गत अधिकारित क्षेत्र, सीमित (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अधिकारण को सौंपा जाता है।

w) "स्थानीय प्राधिकारी" (Local Authority) का तात्पर्य तत्समय प्रकृत किसी विधि के अधीन गठित नगर नियम, नगर पालिका परिवद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत से है।

x) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" (Municipal Solid Waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव विकितसकीय अपशिष्टों को समिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित देशों में पैदा किया जाने वाला पारिज्जिक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

y) "सुविधा के परिचालक" (Operator of a Facility) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अधिकारण भी आता है जो अपने-अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन के लिए नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रतिक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये या पुनः अप्रिक्रिय उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।

2) "पुनर्वापन" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तित करता है, जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

3a) "पृथक्करण" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनर्वापन योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को दर्गों में अलग-अलग करना अभिप्रेत है।

bb) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को अरक्षाई रूप से इस प्रकार छिपा बन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा-करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गम्य को रोका जा सके।

cc) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से दिजायल की गई परिवहन प्रणाली द्वारा यद्यकृता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है जैसे दुर्गम्य, कूड़ा-करकट विद्युतने रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

6- कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, राक नाली, फुटपाथ किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा प्रयोगन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है न छालेगा और न उल्लंघयेगा।

8- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ूपान रखेगा जिनमें से एक में जैव निष्पकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनर्वापनीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त विन्यु ६ के अनुसार संग्रहित जैव निष्पकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनर्वापनीय अपशिष्ट रखाए में एक दिन नगर पालिका के द्वारा निर्धारित समय प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी/सुविधा के प्रबालक (Operator of a Facility) को देना होगा (किन्तु जैव निष्पकरणीय अपशिष्ट तथा अनाशित थीले में रखकर नहीं छाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरों जो समय-समय पर संशोधित थीं जा सकेंगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिनाप सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेंगे।

8- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका/नगर पंचायत से समर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर रोका शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

9- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़-पौधों के कूड़े को परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा सम्भव न हो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करेगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10- नगरीय ठोस अपशिष्ट उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को अलग से जगा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वारा-द्वारा भूगतान हेतु कर्मचारी/सुविधा को प्रबालक को देना होगा।

11- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जैव विकितसा अपशिष्टों को प्रबन्धन जैव-विकितसा अपशिष्टों (प्रबन्धन और हस्तन) नियम, 1988 के अनुसार करेगा, जिन उपचारित जैस-विकितसा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में कहीं मिलायेगा।

12- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्टों को न जलायेगा और न जलवायेगा।

13- नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन पृथक्करण, संग्रहण भण्डारण, परिवहन तथा व्यय से सम्बन्धित स्थल का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14- निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर पाये गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है जो मासिक यूजर चार्जेज के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा के प्रबालक द्वारा उत्काल उत्पादक जा सकेगा या भूजर चार्जेज वसूल किया जा सकेगा। जिसकी प्राप्ति रसीद अपशिष्ट उत्पादक को थी जायेगी। यह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पालिका/सुविधा प्रबालक के खाते में जमा की जायेगी।

15—अनुसूची में दी गयी दरों में द्विवार्षिक 18 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जिसकी गणना ₹ 5/- के पूर्णक में की जायेगी।

16—उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर ब्रॉज़ेज में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची-1 सेवा शुल्क (User Charges)

क्रम संख्या	अपशिष्ट एवं अपशिष्ट संतपादक की सेवा/प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User Charges) की राशि ₹0 में			
		जैविक आजैविक कूड़ा अलग-अलग कर बाहक राक पर्हुआगे पर	भिन्नित कूड़ा लालू कर पर्हुआगे पर	जैविक-आजैविक कूड़ा घर/घोल पर ही अलग-अलग रेटे पर	जो व्यक्ति घर/सौत पर ही भिन्नित कूड़ा वें
1	गैरीबी रेखा से गैरीबी के पर (श्री.पी.एल. कार्ह धारक)	—	05	10	15
2	कम आय वाले घर (श्री.पी.एल. कार्ह धारक के अतिरिक्त 6000 प्रतिमाह तक आय)	05	10	15	20
3	उभरोवत के अतिरिक्त घर	10	20	25	30
4	होटल/लाजिंग/गैर्ल हाउस (20 बेंद तक)	250	350	450	650
5	होटल/लाजिंग/गैर्ल हाउस (20 बेंद से अधिक)	450	550	750	1000
6	धर्मशाला	10	25	40	50
7	बरतावद	500	750	950	1150
8	बेकरी	100	200	150	300
9	कन्यालय	50	75	100	150
10	पर्स्पी एवं फल बिक्री	100	200	100	125
11	रेस्टोरेंट (छोटे)	150	250	350	600
12	रेस्टोरेंट (बड़े)	250	400	500	750
13	पकूल कॉलेज एवं आपाइयो शिक्षण संस्थाएं	100	200	200	200
14	हॉस्पिटल/नर्सिंग हाउस	200	400	200	250
15	गेलिकल स्टोर	150	250	100	125
16	दुकान (आय व छोटी)	50	75	100	180
17	दुकान (बड़ी भोजन आदि)	100	150	250	350
17	बकरीशीप/कबाली	300	500	350	750
18	गन्ने का रस/चुरू चिकना	50	100	125	160
19	मादा एवं गुड़ी बिक्री	100	150	200	300
20	कलीनिक/पैथोलॉजी	100	150	200	300
21	बकरीशाम	100	150	200	300
22	डहान तथा निर्जन सम्बन्धी अपशिष्ट	250	350	450	650

अनुसूची-2 अपशिष्टों की श्रेणी

जैविक (Biodegradable)

हर प्रकार का पका, विना पका हुआ खाद्य अपशिष्ट

सभी एवं फलों के छिलके, फूल दर्पे घरेलू पौधों का कूड़ा

घरेलू जालू से निकली गच्छी

सेनिटरी टॉवल

हड्डों की साधारण

पुनः चक्रवाच (Recyclable)

कामजो तथा हर प्रकार का प्लास्टिक

कार्ड बोर्ड तथा कार्टन

हर प्रकार की पैकिंग

हर प्रकार की डिब्बे (पारिशेक्टमय को छोड़कर)

हर प्रकार का काष्ठ/धातु/रस्त/लकड़ी

फाईल, पुस्तिका, ट्रेटापैक, कैसेट, कम्प्यूटर,

डिस्केट, इलैक्ट्रॉनिक्स पुर्जे, खराब उपकरण

फर्नीचर आदि

घरेलू परिसंकटमय (Hazardous)

घरेलू कैन

इटन सेल, फ्लैशलाईट/कार बैटरी

क्लीं घरेलू रसोई तथा भाली सफाई का सामान औयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद रसायन तथा उनके खाली डिब्बे, सौन्दर्य प्रसाधन तथा उनके खाली डिब्बे

इन्जेक्शन, सुई तथा सिरिज, खसब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे

लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे स्लोसेट बल्ब थर्मसीटर एवं अन्य घरे वाले उत्पाद पेन्ट, तेल, गोद, धौनर तथा उनके डिब्बे फोटोग्राफी के उत्पादन।

शास्ति

सुपरोक्त उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन करने पर नगर पंचायत/नगर पालिका अर्थदण्ड घसूल कर सकेगी जो सेवा शुल्क की निर्धारित दरों का 10 गुना तक अधिकतम हो सकता है। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन, नियम-2016 के उल्लंघन पर ₹० 200 प्रति घन मी० की दर से अर्थदण्ड घसूल किया जायेगा। पिरन्तर उल्लंघन की दशा में ₹० 500 प्रति घन मी० प्रतिदिन की दर से घसूल किया जायेगा।

यह उप नियमावली नगर पंचायत तिलवाडा जनपद-कङ्गप्रयाग (उत्तराखण्ड) के प्रशासक जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग की सहमति पर दिनांक 27/०८/२०१८ के द्वारा पारित की गयी।

रविराज सिंह बंगारी,
अधिकारी अधिकारी,
नगर पंचायत, तिलवाडा।

मंगेश घिल्खाल,
आई.प.एस.
जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग/
प्रशासक नगर पंचायत, तिलवाडा।